पूंजीवादी पुनर्स्थापना के बाद चीन

चीन में पूंजीवाद की पुर्नस्थापना 1976 में, माओ की मृत्यु के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी में चले एक तीखे संघर्ष के बाद हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर यह तीखा संघर्ष समाजवाद के समर्थकों तथा पूंजीवादी पथगामियों के बीच थ ा।

यह संघर्ष चीनी समाज में चल रहे श्रम और पूंजी के संघर्ष को ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में अभिव्यक्त कर रहा था। यह संघर्ष कभी नहीं थमा था। यह अपने आपको कभी खुले तो कभी छिपे रूप में अभिव्यक्त करता था।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इतिहास दो ला इनों के संघर्ष से भरा हुआ है। 1949 में चीन में नवजनवादी क्रांति के सम्पन्न होने के बाद दो लाइनों का संघर्ष छिड़ गया। जिसमें से एक का रास्ता चीन में समाजवाद को सुदृढ़ करने तथा दूसरे का पूंजीवाद की स्थापना की ओर जाता था। पूंजीवादी पथगामी पूंजीवादी उ त्पादन सम्बंधों के प्रतिनिधि थे और 1976 तथा उसके बाद वे चीन में पूंजीवादी उत्पादन सम्बंध कायम करने में सफल हो गये। समाजवादी उत्पादन सम्बंधों का स्थान पूंजीवादी उत्पादन सम्बंधों ने ले लिया।

चीन में पूंजीवादी उत्पादन सम्बंध कायम होते ही मजदूरों और किसान ों से वे अधिकार और सुविधायें क्रमशः छीनी जाने लगी जो उन्हें समाजवादी काल में हासिल थीं। 1976 से जारी इस काल में मजदूर पुनः उजरती गुलामों में तब्दील हो गये हैं। पूंजीवादी भू-स्वामित्व सम्बंध कायम होने से किसानों की व्यापक आबादी गरीबी और बदहाली का जीवन जीने को विवश हो गयी है। इसी तरह मेहनतकश वर्ग की महिलाओं के लिए या तो घृणित घरेलू दासता का जीवन है या फिर वे देशी-विदेशी पूंजी के लिए सस्ते श्रम की स्रोत हैं।

प्रस्तुत लेख में चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के बाद चीनी समाज में आये परिवर्तनों क ा संक्षिप्त लेखा-जोखा लिया गया है। साथ ही इस बात की चर्चा की गयी है कि चीन में आज वर्ग संघर्ष की क्या स्थिति है। लेख के प्रारम्भिक हिस्से में पहले-पहल यह सैद्धान्तिक चर्चा की गयी है कि समाजवादी समाज में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की सम्भावना क्यों छिपी रहती है तथा चीन में पुनर्स्थापना के वस्तुगत कारण क्या थे।

I

समाजवादी समाज के बारे में कुछ बुनियादी बातें

समाजवादी समाज के संदर्भ में कुछ सुस्थापित बातों को यहां पर दोहराया भर जा रहा है। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने समाजवादी समाज के बारे में कम्युनिस्टों की समझ को गहन किया तथा समाजवाद के साम्यवादी समाज में संक्रमण में आने वाली चुनौतियों को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया। मोटे तौर पर ये बातें चीन के समाजवादी काल तथा पूंजीवादी काल के फर्क को समझने के लिए कुछ सूत्र उपलब्ध कराती हैं।

(1) समाजवाद पूंजीवा दी समाज से साम्यवादी समाज के बीच का संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल के दौरान सर्वहारा की तानाशाही कायम रहती है और सर्वहारा नेतृत्व में ही क्रांतिकारी ढंग से समाजवादी समाज क्रमशः साम्यवादी समाज की ओर अग्रसर हो सकता है। समाजवाद इन अर्थों में सुदीर्घ ऐतिहासिक अव स्था होती है।

(2) पूंजीवाद से साम्यवाद तक के संक्रमण काल में हमेशा इस बात की संभावना बनी रहती है कि पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो जाय और सर्वहारा के अधिनायकत्व के स्थान पर पूंजीवादी अधिनायकत्व कायम हो जाये।

(3) पूंजीवाद की उत्पादन के साधनों की निजी स्वामि त्व वाली प्रणाली के बरक्स समाजवाद सार्वजनिक स्वामित्व वाली प्रणाली है। राजसत्ता पर कब्जा करके सर्वहारा निजी स्वामित्व वाली प्रणाली को सार्वजनिक स्वामित्व वाली प्रणाली में तब्दील कर देता है।

(4) पूंजीवाद शांतिपूर्वक समाजवाद में तब्दील नहीं हो सकता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि समाजवादी उत्पादन सम्बंध पूंजीवादी समाज के भीतर पैदा नहीं होते। इनकी स्थापना सर्वहारा के अधिनायकत्व के कायम होने के साथ ही की जाती है।

(5) समाजवाद में लम्बे समय तक पूंजीवादी उत्पादन सम्बंध कायम रहते हैं। पिछड़ी उत्पादक शक्तियों वाले देशों में प्राक् पूंजीवादी उत्पादन सम्बंध भी कुछ समय तक अस्तित्वमान रह सकते हैं। समाजवादी निर्माण प्रक्रिया के दौरान इन व पूंजीवादी उत्पादन सम्बंधों को शीघ्रातिशीघ्र समाजवादी उत्पादन सम्बंधों में रूपान्तरित करना आवश्यक होता है। समाजवादी उत्पादन सम्बंधों की दिशा साम्यवादी उत्पादन सम्बंधों की ओर होती है।

(6) संशोधनवादी विचारधारा यह घोषित करती रही है कि समाजवाद में बुनियादी अंतर्विरोध "विकसित समाजवादी प्रणाली और पिछड़ी उत्पादक शक्तियों" के बीच था। जबकि माओ के अनुसार "समाजवादी समाज में, बुनियादी अंतर्विरोध अभी भी उत्पादन सम्बंधों और उत्पादक शक्तियों के बीच, तथा अधिरचना तथा आर्थिक मूलाधार के बीच ही होते हैं।" (पृष्ठ-13 शंघाई टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी', हिन्दी अनुवाद राहुल फाउण्डेशन)

(7) "समाजवादी उत्पादन सम्बंधों और उत्पादक शक्तियों के बीच, तथा अधिरचना और आर्थिक आधार के बीच संगति और अंतरविरोध एक ऐसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के संघटक तत्व हैं जो समाजवादी समाज को निरंतर आगे बढ़ाती है।" चीन की महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लिखी गयी पुस्तक 'दि शंघाई टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी में यह बात दर्ज है। (हिन्दी अनुवाद, राहुल फाउण्डेशन, पृष्ठ -15)

(8) माओ ने समाजवादी समाज के बारे में बताया है, "समाजवादी समाज एक अपेक्षाकृत सुदीर्घ ऐतिहासिक अवधि होती है। समाजवाद की ऐतिहासिक अवधि में वर्ग, वर्ग अंतर्विरोध और वर्ग संघर्ष मौजूद रहते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी दो रास्तों के बीच का संघर्ष मौजूद रहता है, पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का खतरा बरकरार रहता है"। (पृष्ठ 16,वही)

(9) लेनिन के शब्दों में,'समाजवादी राज्य बुर्जुआ वर्ग के बिना बुर्जुआ राज्य होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य को, अब भी बुर्जुआ अधिकारों की रक्षा करनी होती है। (पृष्ठ 36, वही)

(10) समाजवादी समाज में माल व्यवस्था, मुद्रा के जरिये विनिमय, काम के अनुसार वितरण के प्रचलन और मजदूर तथा किसान, शहर तथा गांव एवं मानसिक तथा शारीरिक श्रम के बीच के बुनियादी अंतरों की मौजूदगी के चलते लोगों के बीच आपसी सम्बंधों में बुर्जुआ अधिकार काफी हद तक मौजूद रहता है और वितरण में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। समाजवाद की ऐतिहासिक अवस्था में इस तरह के बुर्जुआ अधिकार को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और कुछ पक्षों में इसे राज्य द्वारा वैधिक मान्यता और संरक्षण भी मिला होता है। इसे सर्वहारा के अधिनायकत्व द्वारा केवल सीमित किया जा सकता है जो इतिहास के रंगमंच से बुर्जुआ अधिकार के पूरी तरह खात्मे की स्थितियां निर्मित करने के सक्रियता से प्रयास जारी रखता है।" (वही, पृष्ठ 14)

(11) माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कहा था, "...लेनिनवादी दृष्टिकोण के अनुसार, किसी एक समाजवादी देश की आखिरी विजय के लिए न सिर्फ इस बात की जरूरत होती है कि उसी देश का सर्वहारावर्ग और विशाल जनसमुदाय प्रयत्न करे, बल्कि यह तकाजा भी है कि विश्व-क्रांति भी विजय प्राप्त करे, पूरी पृथ्वी पर मानव द्वारा मानव का शोषण करने की व्यवस्था का खात्मा हो, जिससे कि सारी मानव जाति मुक्त हो जाय।" (माओ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नवीं राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रस्तुत रिर्पोट,'राजसत्ता और क्रान्ति,' अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन)

II

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति और उसका योगदान

मई 1966 में माओ के नेतृत्व में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति प्रारम्भ हुई। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की पृष्ठभूमि में सोवियत संघ में 1956 में हुई पूंजीवाद की पुनर्स्थापना तथा चीन में पूंजीवादी पथगामियों का बढ़ता वर्चस्व था। चीन के पूंजीवादी पथगामी सोवियत संघ के संशोधनवादियों से बल और प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। चीनी समाज में मौजूद प्रतिक्रियावादी वर्ग तथा इन वर्गों को पालने-पोसने वाली भौतिक परिस्थितियां पूंजीवादी पथगामियों को अनुकूल

अवसर प्रदान कर रही थीं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में पूंजीवादी पथगामियों की संख्या अच्छी खासी थी और वे शीर्ष नेतृत्वकारी निकायों में भी मौजूद थे।

माओ जहां सर्वहारा लाइन को नेतृत्व दे रहे थे वहीं ल्यू शाओ-ची, लिन-पियाओ बुर्जुआ लाइन के अगुआ थे। एक समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में दो सदर मुकाम-सर्वहारा तथा बुर्जुआ-कायम थे।

'66 -'74 तक माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के वर्षों के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, सशस्त्र सेनाओं व जनता को नेतृत्व प्रदान किया। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान दो विरोधी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली दिशाओं के बीच तीखा संघर्ष चला।

ल्यू-शाओ-ची तथा लिन-पियाओ ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तथा राजसत्ता पर कब्जे के लिए हरदम कोशिश की तथा षड्यंत्रों का सहारा लिया। सर्वहारा अधिनायकत्व को बुर्जुआ अधिनायकत्व तथा मार्क्सवादी- लेनिनवादी पार्टी को संशोधनवादी फासिस्ट पार्टी में बदल डालने की हरचन्द कोशिश की। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने पार्टी तथा राज्य की हिफाजत की तथा यह साबित किया कि पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने का यही एक कारगर तरीका है।

माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता को इन शब्दों में बताया हैं,

> *"मौजूदा महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति सर्वहारा अधिनायकत्व को सुदृढ़ बनाने, पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की रोक थाम करने और समाजवाद का निर्माण करने के लिए निहायत जरूरी है और अत्यंत समयानुकूल है।" (माओ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नवीं कांग्रेस में प्रस्तुत रिपोर्ट, राजसत्ता और क्रांति (महान सर्वहारा क्रांति के कुछ दस्तावेज), पृष्ठ-3, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन)*

माओ की महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा में यह बात मौजूद है कि महज एक सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति से यह सुनिश्चित नहीं होगा कि समाजवाद बना रहे और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना न हो। माओ ने बार-बार इस बात को बताया है कि समाजवाद में वर्ग, वर्ग-अंतरविरोध और वर्ग संघर्ष मौजूद रहते हैं। बुर्जुआ वर्ग और उसके प्रतिनिधि पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाते हैं। चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना ने इस बात को साबित भी किया। इसलिए यह बात बहुत बेतुकी है कि चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति हो जाने के बाद भी पूंजीवाद की पुनर्स्थापना क्यों हो गयी। माओ का कहना है,

> *" मौजूदा महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति महज पहली है। अभी आगे और कई ऐसी क्रांतियां होगी। क्रांति में कौन विजयी होगा इसका निर्धारण केवल एक लम्बे ऐतिहासिक काल के बाद ही हो सकेगा। यदि इसे ठीक से संचालित नहीं किया गया, तो पूंजीवादी पुनर्स्थापना किसी भी समय हो सकती है। सभी पार्टी सदस्यों और पूरी जनता को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि एक या दो या तीन या चार महान सांस्कृतिक क्रांतियां कर लेने के बाद ही सारी चीजें एकदम ठीक-ठाक हो जायेंगी। यह पूरी तरह सुनिश्चित रखें कि सतर्कता कभी ढीली न पड़े।" (माओ, 'दि शंघाई टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी', पृष्ठ-19, खण्ड-दो, हिन्दी अनुवाद, राहुल फाउण्डेशन)*

चीन के पूरे समाजवादी काल में सर्वहारा और बुर्जुआ लाइन के बीच संघर्ष बहुत तीखा था। हर कहीं की तरह चीन में भी बुर्जुआ लाइन अक्सर ही मार्क्सवादी शब्दावली का आवरण ओढ़ कर आती थी। सर्वहारा लाइन और बुर्जुआ लाइन हर सवाल पर दो विपरीत दिशाओं में बंटी होती थी। जाहिर सी बात है सर्वहारा लाइन जहां समाजवाद को, सर्वहारा के अधिनायकत्व सुदृढ़ करने की होती थी वहां बुर्जुआ लाइन की कोशिश पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और पूंजीपति वर्ग की सत्ता कायम करने की होती थी।

कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। 1949 में क्रांति के बाद कृषि के सहकारीकरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। ल्यू शाओ-ची, चेन पो-ता इस बात के पक्षधर थे कि चीन में कृषि का यंत्रीकरण पहले होना चाहिए सहकारीकरण बाद में, माओ ने इस लाइन का विरोध किया और कहा चीन की तात्कालिक परिस्थितियों में कृषि में बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से पहले सहकारीकरण होना चाहिए। कृषि के सहकारीकरण की लाइन भू-स्वामियों व धनी किसानों के विरुद्ध समझौताहीन संघर्ष की वकालत करती जबकि यंत्रीकरण की लाइन उनके हितों को साधती थी।

1952 से ही ल्यू शाओ-ची देहात में 'चार स्वतंत्रताओं' की बात कर रहा था। उसका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक शक्तियों को अपना काम करने की छूट होनी चाहिये। उसकी चार स्वतंत्रताओं में जमीन को खरीदने-बेचने, जमीन पर मनमाफिक फसल उगाने, उधार प्रणाली, मुक्त बाजार की स्वतंत्रता' शामिल थी। जाहिर सी बात है कि ल्यू शाओ-ची की 'चार स्वतंत्रताएं' धनी किसान और भू-स्वामी वर्ग को ही भा सकती थीं।

माओ जहां लगातार बता रहे थे कि चीन में यह सवाल अभी तय नहीं हुआ है कि समाजवाद विजयी होगा या पूंजीवाद वहां ल्यू-शाओ-ची 1956 में ही यह दलील पेश कर रहा था कि 'चीन में यह सवाल हल हो चुका है। माओ ल्यू शाओ-ची की लाइन का विरोध करते हुए इस बात को सामने ला रहे थे कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक मिल्कियत कायम हो जाने के बाद भी वर्ग और वर्ग संघर्ष मौजूद रहेंगे। ल्यू शाओ-ची माओ के विरुद्ध दावा कर रहा था कि 'समाजवादी रूपान्तरण में निर्णायक जीत हासिल की जा चुकी है ... हमारे देश में सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच का अंतरविरोध बुनियादी तौर पर हल हो चुका है।

इसी तरह के तमाम अन्य उदाहरणों द्वारा यह बात स्थापित की जा सकती है कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति के पहले सर्वहारा और बुर्जुआ लाइन के बीच तीखा संघर्ष मौजूद था। यह संघर्ष जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद था। इन अर्थों में देखा जाय तो सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष के अनिवार्य परिणाम के रूप में आयी। सांस्कृतिक क्रांति कहीं से भी आकस्मिक नहीं थी और कहीं से भी कुछ व्यक्तियों के बीच सत्ता पर कब्जे की लड़ाई नहीं थी।

सांस्कृतिक क्रांति एक राजनीतिक क्रांति थी जो कि सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपति वर्ग और शेष बचे शोषक वर्ग के सदस्यों के खिलाफ थी।

सांस्कृतिक क्रांति ने इस बात का खण्डन किया कि समाजवाद का विकास बुनियादी रूप से उत्पादन शक्तियों के विकास पर निर्भर है। 'उत्पादन शक्तियों के विकास' की लाइन एक बुर्जुआ लाइन थी जो कि वर्ग संघर्ष से किनाराकशी करती थी और बुर्जुआ वर्ग की हिफाजत करती थी और गुपचुप और छिपे ढंग से उसका मार्ग प्रशस्त करती थी। बुर्जुआ लाइन का प्रतिनिधित्व करने वाले ल्यू शाओ-ची की लाइन थी कि समाजवाद में विकसित समाजवादी प्रणाली और पिछड़ी उत्पादन शक्तियों के बीच बुनियादी अंतरविरोध होता है। जबकि सर्वहारा लाइन का कहना था कि समाजवादी समाज में अभी भी बुनियादी अंतरविरोध उत्पादन सम्बंधों और उत्पादक शक्तियों तथा अधिरचना और आर्थिक मूलाधार के बीच होता है।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के उद्देश्य के बारे में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का बिन्दु 14 "क्रांति को दृढ़ता से चलाओ और उत्पादन कार्य को बढ़ावा दो" कहता है,

> *"महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य है लोगों की विचारधारा का क्रांतिकारी रूपान्तर करना और इसके फलस्वरूप कार्य के हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छा और कम खर्च में नतीजे हासिल करना। अगर आम जनता को पूरे तौर से जागृत कर दिया जाय तथा यथोचित प्रबंध कर लिया जाय तो सांस्कृतिक क्रांति तथा उत्पादन कार्य दोनों को ही, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाये बगैर, चलाया जा सकता है और साथ ही अपने तमाम कार्य में ऊंचे गुण की गारंटी की जा सकती है।*
>
> *" यह महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति हमारे देश की सामाजिक उत्पादन-शक्तियों को विकसित करने वाली एक जबरदस्त प्रेरक शक्ति है।" ('महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के बारे में' 8 अगस्त 1966 को स्वीकृत, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का फैसला, हिन्दी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित)*

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने इस बात को साबित किया कि वर्ग संघर्ष को जारी रखने और लोगों की विचारधारा के क्रांतिकारी रूपान्तरण से उत्पादन शक्तियों के विकास का मार्ग बहुत तेजी से खुल जाता है। 'शंघाई पॉलिटिकल इकॉनामी' में इन वर्षों के दौरान कृषि में मशीनीकरण तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि की बातें इन शब्दों में दर्ज हैं,

> *"अध्यक्ष माओ की सर्वहारा क्रांतिकारी लाइन के मार्गदर्शन में, और विशेष तौर पर महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन के कृषि मशीनीकरण में तीव्र विकास हुआ है। 1965 की तुलना में 1973 में ग्रामीण इलाकों में विद्युत-उपभोग में 2.8 गुने की, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 1.9 गुने की, बड़े और मझौले ट्रैक्टरों की संख्या में 2.2 गुने की तथा हस्तचालित ट्रैक्टरों की संख्या में 75 गुने की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में, कुल कृषि भूमि में मशीनी साधनों द्वारा जोते जाने वाले हिस्से में 70 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। विद्युतीकृत जल-प्रवाह और सिंचाई साधनों में 2.8 गुने की वृद्धि हुई है।'' (पृष्ठ 136-137, वही)*
>
> *"ल्यू शाओ-ची की संशोधनवादी लाइन के हस्तक्षेप और विध्वंसक भूमिका के चलते, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के पहले, सियाङ काउण्टी में, जहां ताचाई ब्रिगेड स्थित है, ताचाई से सीखने का जन आंदोलन शुरू नहीं हो सका। इससे कृषि-उत्पादन के विकास की गति अत्यंत मद्धम रही। फिर भी काउण्टी में खाद्यान्न का कुल उत्पादन सात-आठ करोड़ जिन के आसपास था। राज्य को सालाना लगभग 70 लाख जिन खाद्यान्न बेचा जाता था। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने सियाङ काउण्टी के दृष्टिकोण को बदल दिया। 1967 से नई शुरूआत हुई और पूरी काउण्टी में ताचाई से सीखने का जन-आंदोलन जबरदस्त ढंग से उठ खड़ा*

हुआ। इसने लिन पियाओ की संशोधनवादी लाइन के हस्तक्षेप और तोड़फोड़ की कार्यवाई का भी विरोध किया। समूची काउण्टी की जनता ने आकाश पाताल एक कर दिया, पहाड़ों और नदियों को रूपान्तरित कर डाला और सियाङ काउन्टी के 'भू क्षेत्र का नक्शा बदल डाला। कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा। खाद्यान्न का उत्पादन तीन वर्षों में दुगना और पांच वर्षों में तिगुना हो गया। 1971 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 24 करोड़ जिन हो गया, जो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के पहले के सर्वाधिक उत्पादन से भी तिगुना अधिक था। राज्य को माल के रूप में बेचा जाने वाला खाद्यान्न 8 करोड़ जिन हो गया, जो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के पहले के सबसे अच्छी फसल वाले वर्ष की तुलना में भी दस गुना था।" (पृष्ठ 139-140, वही)

इसी तरह औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक विकास दर सांस्कृतिक क्रांति के पूरे दौर (1966-76) में दस प्रतिशत से अधिक रही है।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का महत्व इस बात में है कि यह सर्वहारा अधिनायकत्व को सुदृढ़ करती है, पूंजीवाद की पुनर्स्थापना को रोकती है, समाजवाद के निर्माण के साथ यह साम्यवाद की स्थापना के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने यह स्थापित किया कि क्रांतिकारी विकास के लिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्रों में बुर्जुआ वर्ग पर चौतरफा अधिनायकत्व लागू किया जाना चाहिए तथा ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जानी चाहिए कि बुर्जुआ सहित सभी शोषक वर्गों का जीवित रहना असम्भव कर दिया जाय और इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि नये बुर्जुआ तत्व भी न पैदा हों। सर्वहारा वर्ग कई सांस्कृतिक क्रांतियों के जरिये ही अपने अधिनायकत्व को कायम रख सकता है। सर्वहारा के अधिनायकत्व की एक ऐतिहासिक अवधि के बाद ही यह संभव हो सकता है कि सर्वहारा अपने ऐतिहासिक मिशन साम्यवाद के लक्ष्य को हासिल करे।

III

पुनर्स्थापना के कारणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी

चीन में समाजवादी व्यवस्था के अंतरविरोधों को सामने लाते हुए माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कहा था,

"एक शब्द में तो चीन एक समाजवादी देश है। मुक्ति के पूर्व यह एक पूंजीवादी देश के समान ही था। अब भी हमारे यहां आठ ग्रेडों वाली वेतन-व्यवस्था, काम के अनुसार वितरण और मुद्रा के जरिये विनिमय लागू है, और यह सब पुराने समाज से ज्यादा भिन्न नहीं है। जो चीज भिन्न है, वह यह कि हमारी स्वामित्व प्रणाली बदल गयी है। ...

"हमारे देश में अब भी माल व्यवस्था प्रचलित है, वेतन व्यवस्था भी असमान है, जैसे कि आठ ग्रेडों वाले वेतनमान, और इस तरह की कई चीजें। सर्वहारा अधिनायकत्व के अंतर्गत ऐसी चीजों को सीमित ही किया जा सकता है।" (पृष्ठ-10, वही)

जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है समाजवादी समाज में वर्ग, वर्ग-अंतरविरोध और वर्ग संघर्ष मौजूद रहते हैं। चीनी समाज में भी समाजवादी काल के समय यही स्थिति थी। पूरे समाजवादी काल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वर्ग-अंतरविरोध मौजूद न रहे हों। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की विजय के काल में भी बुर्जुआ तत्वों की पैदाइश की जमीन बरकरार थी।सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग दोनों की मौजूदगी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में थी। इन दोनों वर्गों के दो केन्द्र, दो सदर मुकाम पार्टी में मौजूद थे। ये एक-दूसरे के खिलाफ भीषण संघर्ष में उलझे हुए थे। माओ के नेतृत्व में सर्वहारा सदर मुकाम ने पार्टी के चरित्र और सर्वहारा सत्ता की रक्षा की हुई थी। माओ की मृत्यु के बाद सर्वहारा सदर मुकाम कमजोर पड़ गया और 1976 में देंग श्याओ-पिंङ के नेतृत्व में बुर्जुआ वर्ग पार्टी और सत्ता पर काबिज हो गया।

सर्वहारा तत्वों व बुर्जुआ तत्वों के बीच समाजवादी काल में तीखे संघर्ष को अभिव्यक्त करने वाली घटनायें रोज घटती थी। बुर्जुआ सदर मुकाम को नेतृत्व देने वाला पार्टी केन्द्र तथा राजसत्ता में आसीन लोग ऐसी नीतियां बनाते व लागू करते थे जो उनके आधार को मजबूत करे। कम्युनिस्ट पार्टी व जन संगठनों में बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधियों की भर्ती के लिए बुर्जुआ सदर मुकाम सदैव प्रयत्नशील रहता था। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है।

"1964 व 1965 में यकायक यूथ लीग ने अपने दरवाजे खोल दिये और एक झटके में 85 लाख नये सदस्यों की भर्ती कर दी। जो कि इसके इतिहास में विशालतम थी। यह भर्ती बिना वर्ग उत्पत्ति की जांच किये केवल औपचारिक आवश्यकताओं के आधार पर कर दी गयी। भू-स्वामी और धनी किसानों की संतानों यहां तक कि प्रतिक्रांतिकारियों की औलादें भारी पैमाने पर इसमें शामिल हुए। इतने विशाल पैमाने पर अचानक इतनी भर्ती वास्तव में दक्षिणपंथी धड़े द्वारा माओ और उनकी युवा नीति पर हमला थी। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान इसने इतनी अधिक और जटिल युवा 'समस्या' को प्रस्तुत किया। यूथ लीग को 1966 के उत्तरार्द्ध में निलम्बित कर दिया गया तथा इसे केवल 1971 में जाकर ही पुनः बहाल किया गया।" (Han Suyin, 'Wind in the tower', पृष्ठ-274, हिन्दी अनुवाद हमारा, Published in 1978 by Triad/Panther Books)

यह कम दिलचस्प बात नहीं है कि आज की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व हू जिन ताओ सहित इसी यूथ लीग की पैदाइश है।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान यह साफ और तीखे तौर पर सामने आ गया था कि चीनी समाज में बुर्जुआ और यहां तक कि कंफ्यूशियस के विचारों की मौजूदगी है और अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। इसी तरह मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम, मजदूर और किसान, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच गहरी असमानताएं हैं। इन असमानताओं को अभिव्यक्ति देने वाले वैधिक अधिकार भी मौजूद हैं। साथ ही चीन में माल व्यवस्था कायम थी। माल व्यवस्था के प्रचलन के चलते मूल्य का नियम काम करता है और मूल्य का नियम वास्तव में बुर्जुआ अधिकार को मूर्त रूप देता है। चीन में पार्टी और सत्ता पर सर्वहारा की पकड़ के ढीली होते ही इस बात की सम्भावना पैदा हो गयी कि बुर्जुआ वर्ग जो कि पार्टी और समाज में मौजूद था अपने आपको पहले छद्म रूप में और कालान्तर में खुले और वास्तविक रूप में प्रकट कर सके। देंङ श्याओ पिंङ ने बुर्जुआ व्यवस्था को कायम करने के लिए यही तरीका अपनाया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान देंङ-श्याओ पिंङ की तीखी आलोचना की गयी थी और उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया था। 1974 में आत्म आलोचना करके तथा कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष नेता के सहयोग से ही वह वापस आ सका। ध्यान देने वाली बात यह है कि देंङ श्याओ पिंङ जैसा घोर पूंजीवादी पथगामी लम्बे समय तक पार्टी महासचिव रहा था। '74-'76 के काल में ऐसे कई तत्व स्थानीय स्तर से लेकर केन्द्रीय स्तर तक में आत्म आलोचना करते हुए, अपने वर्गीय मंसूबों को छुपाते हुए पार्टी में वापस आये थे। देंङ श्याओ पिंङ व अन्य पूंजीवादी पथगामियों ने माओ की मृत्यु के बाद तेजी से पार्टी और सशस्त्र सेनाओं में अपने जैसे तत्वों को भर्ती की। माओ के समर्थकों या सर्वहारा लाइन के पक्षधरों को 'अति वामपंथी' 'अराजकता फैलाने वाले' आदि कह कर पार्टी से बाहर कर दिया गया और कइयों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। हुआ-कुआ फेंङ जैसे मध्य मार्गी ने जो माओ की मृत्यु के बाद नेतृत्व में आया देंङ श्याओ पिंङ की राह सुगम बनायी। वर्ग संघर्ष के स्थान पर तीन दुनिया का वर्ग सहयोगवादी सिद्धान्त प्रस्तुत कर उसने देंङ के "बाजार समाजवाद" का मार्ग प्रशस्त किया।

IV

पुनर्स्थापना के बाद चीनी समाज

1976 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तथा सत्ता पर पूंजीवादी पथगामियों का कब्जा हो गया। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद एक समय ऐसा समय रहा है जब समाजवादी पथगामियों तथा पूंजीवादी पथगामियों के बीच तीखा संघर्ष चला था। शीर्ष माओवादी नेताओं को देंङ श्याओ पिंङ ने चार का गिरोह (Gang of four) कह कर बदनाम किया तथा उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पार्टी और सत्ता में से चुन-चुन कर देंङ ने समाजवादी पथगामियों को अलग कर दिया। देंङ ने सांस्कृतिक क्रांति को लांछित करना प्रारम्भ किया। उसने यह झूठे आरोप लगाये कि सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उत्पादन गिर गया था तथा माओ की वर्ग संघर्ष की नीति ने उत्पादक शक्तियों को नुकसान पहुंचाया तथा समाज में अव्यवस्था और हिंसा फैलायी। पार्टी, सत्ता व सशस्त्र सेनाओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेने के बाद देंङ श्याओ पिङ ने पूंजीवाद का रास्ता साफ करने के लिए एक के बाद एक पूंजीवादी सुधारों की घोषणा की।

देंङ श्याओ पिंङ ने सांस्कृतिक क्रांति की भर्त्सना लगातार की और उसने 'उत्पादन शक्तियों के विकास' वाली लाइन को आगे बढ़ाया। देंङ ने कहा था कि उत्पादक शक्तियों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि बाजार का उपयोग किया जाय। देंङ की विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाले कुछ जुमले इस प्रकार हैं; ' कुछ लोग दूसरों से

पहले अमीर बन जायेंगे', 'धनी होना शानदार है', 'इस बात से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद जब तक कि वह चूहों को पकड़ती रहती है,' 'अपने को धनी बनाओ' इत्यादि।

देंङ के बारे में कभी माओ ने कहा था :

"इस व्यक्ति ने वर्ग संघर्ष को ग्रहण नहीं किया है; इसने कभी इस बुनियादी सूत्र का उल्लेख नहीं किया। अभी भी 'सफेद बिल्ली, काली बिल्ली' वाली इसकी विषय वस्तु (Theme) साम्राज्यवाद और मार्क्सवाद में कोई फर्क नहीं करती है।"

"यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद से कुछ नहीं समझता, यह बुर्जुआ का प्रतिनिधित्व करता है।" ('And Mao makes - 5,' पृष्ठ- 46, published by, BANNER press , Sept-1976, अनुवाद हमारा)

मार्टिन हार्ट लैण्ड्सबर्ग और पॉल बर्केट (Martin Hart- Landsberg And Paul Burkett) ने 1978 के बाद चली आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को तीन कालखण्डों में बांटा है। सुविधा के लिए इस विभाजन को हम भी अपना ले रहे हैं। संक्षेप में इन कालखंडों में कुछ बुनियादी सुधारों की चर्चा करेंगे। बंटवारे का आधार सुधारों की मात्रा व गति है अन्य कुछ नहीं।

सुधार प्रक्रिया का प्रथम चरण(1978 से 83) : चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दिसम्बर 1978 में पार्टी के तीसरे प्लेनम में बाजार की शक्तियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा इसे 'समाजवादी आधुनिकीकरण के लिए ऐतिहासिक बदलाव' (historic shift to socialist modernization) कहा गया। इसके तहत केन्द्रीयकरण के स्थान पर क्षेत्रीय और प्रान्तीय निकायों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गयी, राजकीय फर्मों के मैनेजरों को उत्पादन संगठित करने के लिए अधिक अधिकार प्रदान किये गये, राजकीय फर्मों तथा स्थानीय सरकारी निकायों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया वे लाभ कमायें, व्यक्तिगत नेतृत्व को बढ़ावा दिया गया, इत्यादि। यह सुधार 1979 की शुरूआत में कुछ चुने हुए शहरी क्षेत्रों में लागू किये गये।

1983 में चीन की राज सत्ता ने राजकीय निकायों को इस बात के आदेश दिये कि वे नये मजदूरों को संविदा के आधार पर सीमित समय के लिए रखें। इन नये मजदूरों को उन सभी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर दिया गया जो कि स्थायी मजदूरों को हासिल थीं। अप्रैल 1987 तक चीन में राजकीय उपक्रमों में संविदा मजदूरों की संख्या 75 लाख से ऊपर थी जो कि औद्योगिक मजदूरों की कुल संख्या का आठ फीसदी थी। इसी तरह राजकीय संस्थाओं के करीब 60 लाख मजदूरों को संविदा मजदूरों में बदल दिया गया।

सितम्बर 1980 सरकार ने कृषि में सामूहिकीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। ऐसे कदम उठाये गये जिसे तहत कम्यून आधारित उत्पादन व्यवस्था को निजी परिवार आधारित व्यवस्था में बदल दिया गया। 1983 तक 98 फीसदी परिवार इसी नयी व्यवस्था के तहत बाजार के लिए उत्पादन कर रहे थे। अभी यद्यपि जमीन पर सामूहिक मालिकाना कायम था। 1983 व 1984 में सरकार के नये कानूनों के तहत उन लोगों को जिनके पास संविदा की भूमि थी, इस बात का अधिकार दे दिया गया कि वे उजरत पर मजदूरों को रख सकते हैं और किराये पर जमीन किसानों को दे सकते हैं। 1980 के दशक के अंत से ऐसी संविदा जमीन को किराये पर देने, बेचने और अपने उत्तराधिकारी को देने का अधिकार दे दिया गया।

1982 में कम्यूनों को नष्ट करना शुरू कर दिया गया। उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार नये स्थापित किये गये व 'नगर क्षेत्र व ग्राम उद्यमों' (Township and Village enterprises- TVE's) को दिये गये । TVE's की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 1987 में जहां इनकी संख्या 15 लाख थी वहां 1993 तक इनकी संख्या दो करोड़ पच्चीस लाख से ऊपर हो गयी थी । ये छद्म वेश धारण किये हुए निजी उद्यम ही थे। देखने में ही इनका रूप सामूहिक था। ये मजदूरों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखते थे और उन्हें इस बात के लिए बाध्य करते थे कि वे अन्य TVEs से मुकाबला करें तथा मुनाफा कमाने में योगदान दें। TVE's सस्ते श्रम के स्रोत का इस्तेमाल करने के नये जरिये बन गये थे। अपनी स्थापना के बाद से ये रोजगार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्यम बनते चले गये। बाद के समय में इनमें से कई ने विदेशी पूंजी के साथ संयुक्त उद्यम लगाये।

1982 में चीन द्वारा अपनाये गये नये संविधान में मजदूरों के हड़ताल पर जाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।

1979 में चीन के दक्षिण-पश्चिम इलाके में चार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किये गये।

सुधार प्रक्रिया का द्वितीय चरण(1984 -91) : 1984 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 'नियोजित माल अर्थव्यवस्था' का जुमला उछाला और इसका अर्थ था राजकीय उपक्रमों पर केन्द्रीय नियंत्रण का ढीला करना और इन उपक्रमों को अपने संसाधन स्वयं जुटाने पर जोर देना अक्टूबर 1984 में एक पार्टी आदेश के तहत अधिकांश उपभोक्ता

तथा कृषि सामग्रियों के मूल्यों को निर्धारित करने के काम को बाजार की शक्तियों के हवाले कर दिया गया। केवल कोयला, तेल, स्टील जैसी चीजों के मूल्य निर्धारण को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में रखा।

सुधारों के इस दूसरे चरण में सरकार ने श्रम शक्ति को सस्ते माल में बदलने की प्रक्रिया को जारी रखा। 1984 तक स्थायी राजकीय मजदूर (ग्रामीण औद्योगिक मजदूर सहित) कुल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के चालीस फीसदी ही रह गये थे। विभिन्न उपक्रमों में मैनेजरों को मजदूरों को बर्खास्त करने के और अधिक अधिकार दे दिये गये।

दूसरे चरण के सुधारों की मुख्य विशेषताओं में से एक थी ऐसे विशेष क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर घोषणा होना जहां विदेशी निवेश किया जा सकता था। यह नीति माओ की आत्मनिर्भरता की नीति के एकदम खिलाफ थी। चीन के नये शासक चीन के विकास के लिए विदेशी व साम्राज्यवादी पूंजी पर अधिक से अधिक निर्भर होने की ओर इस चरण में बढ़े। 1984 में 14 तटीय शहरों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया। चार ऐसे विशेष क्षेत्र इसके पहले से ही कार्य कर रहे थे। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में पेश किया जाने लगा।

अक्टूबर 1987 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 'चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद' का जुमला उछाला जिसके तहत चीनी अर्थव्यवस्था को विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में बिंदास ढंग से प्रवेश करना था तथा इसका लक्ष्य चीन की अर्थव्यवस्था को "निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था" में तब्दील करना था।

बाजार की शक्तियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 1985 -87 के बीच मुद्रास्फीति की दर 8 % वार्षिक हो गयी और 1988 व 1989 में कीमतों में 18 % की वृद्धि दर्ज की गयी। बीजिङ और शंघाई जैसे शहरों में यह वृद्धि और अधिक थी। समाजवादी चीन में महंगाई, मजदूरी में गिरावट, व्यापार घाटा, बजट घाटा जैसी चीजें अनजानी थीं अब वे अन्य पूंजीवादी व्यवस्थाओं की तरह 'चीनी विशेषता वाले समाजवाद' के साथ चिपक गयीं।

सुधारों के इस पूरे दौर में और आज भी चीनी शासकों ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाकर रखा हुआ है। यह, चीन के शासकों ने सोवियत संघ के अनुभव व तीसरी दुनिया के देशों में खुली पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने से पैदा होने वाली सामाजिक उथल-पुथल के उदाहरणों से सीखा है। सुधारों को एक झटके में लागू करने के बजाय क्रमिक रूप में लागू किया गया। जरूरत पड़ने पर कुछ समय तक (एक या दो वर्ष) सुधारों की गति को थोड़ा धीमा भी किया गया।

सुधार प्रक्रिया का तृतीय चरण (1991 से अब तक): अक्टूबर 1992 में चीनी पार्टी की चौदहवीं कांग्रेस में 'चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद' को लागू करने का अपना इरादा दुहराया गया। इस इरादे की एक अभिव्यक्ति 1992 में इस प्रकार हुई। चीनी शासकों ने एक आज्ञप्ति (decree) के जरिये इस बात पर बहस करने पर पाबन्दी लगा दी कि चीन समाजवाद की ओर जा रहा है या पूंजीवाद की ओर। बाजार की शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। राजकीय उद्यमों (SOE) की चीन की अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय भूमिका को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाने लगे। सरकारी क्षेत्र को सिकोड़ने के लिए निजी उपक्रमों को तेजी से प्रोत्साहन दिया जाने लगा।

इस चरण के सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान चीन के शासकों की विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य बनने की इच्छा और उसके लिए कोशिशों का था। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के लिए चीन को जो जरूरी अर्हतायें पूरी करनी थीं। वे उसने तमाम किस्म के सुधारों के जरिये 2001 में पूरी कर लीं। दिसम्बर 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया।

इस चरण के सुधारों में एक अन्य महत्वपूर्ण चीज थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप पूरी तरह चीन को ढालना। शेयर मार्केट व्यवस्था नब्बे के दशक से पहले तक चीन में अपनी जड़ नहीं जमा सकी थी। 1990 में चीन की सरकार ने इसकी शुरूआत शेनजेन स्टॉक एक्सचेन्ज को खोलकर की। इसके अगले वर्ष 1991 में शंघाई स्टॉक एक्सचेन्ज खोला गया।

सुधारों के इस चरण में चीन में विदेशी पूंजी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई। 1990 में जहां यह 3.49 अरब डालर था वहां यह 2002 आते-आते 52.77 अरब डालर पहुंच गया। (कृपया तालिका -1 देखें)। इसी तरह सकल निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत 1985 में जहां 1.1% था वहां 2002 में यह बढ़कर 10.4 % हो गया।बीच के कुछ वर्षों में तो यह 15 % के आसपास तक रहा है। यह परिघटना दिखा रही है कि चीन आज साम्राज्यवादियों से लेकर दक्षिण कोरिया के पूंजीपतियों तक की पसंदीदा जगह बन गया है। पसंदीदा जगह बनाने के लिए चीनी शासकों ने कोई कसर छोड़ी भी नहीं है। अत्यंत सस्ता और लचीला श्रम, श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार न होना, तथा मजदूरों को स्वतंत्र ट्रेड-यूनियन बनाने पर प्रतिबंध, (मजदूर सरकारी ट्रेड-यूनियन के अतिरिक्त किसी अन्य यूनियन के सदस्य नहीं हो

सकते हैं क्योंकि मजदूर यूनियन बनाना गैर कानूनी है), सामाजिक सुरक्षा में उन्हें किसी किस्म का योगदान नहीं करना और भारी पैमाने पर मुनाफे कमाना इत्यादि।

तालिका -1

चीन के लिए प्रत्य क्ष विदेशी निवेश

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अरब डालर में)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वार्षिक वृद्धि दर (% में)	सकल निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुपात (% में)
1985	1.03	-8.4	1.1
1986	1.43	38.3	1.6
1987	1.67	17.1	1.7
1988	2.34	40.4	1.9
1989	2.61	11.5	2.3
1990	3.49	33.7	3.5
1991	4.37	25.2	3.9
1992	11.01	151.9	7.3
1993	27.52	150	12.3
1994	33.77	22.7	17.3
1995	37.52	11.1	15.4
1996	41.73	11.2	14.9
1997	45.28	8.5	14.9
1998	45.46	0.4	13.6
1999	40.29	-11.4	11.3
2000	40.8	1.3	10.4
2001	46.77	14.6	10.5
2002	52.77	12.8	10.4

स्रोतः National Bureau of Statistics of China,China Statistical Year Book 2002, AMR (July- Aug. 2004) में उद्धृत,पृष्ठ-115

तालिका- 2

चीन के कुल निर्यात व व्यापार में विदेशी धन प्राप्त संस्थानों का हिस्सा

वर्ष	निर्यात में हिस्सा (% में)	कुल व्यापार में हिस्सा (% में)
1990	17.4	12.6
1991	21.4	16.8
1992	26.3	20.5
1993	34.3	27.5
1994	37	28.7
1995	39.1	31.5
1996	47.3	40.7
1997	47	41
1998	46.7	44.1
1999	48.4	45.5
2000	49.9	47.9
2001	50.8	50.1

स्रोत : July- Aug- 2004, Analytical Monthly Review, Table-6, page 118

सन् 2003 तक स्थिति यह पहुंची हुई थी कि फॉरचून सूची में दर्ज 500 विशाल निगमों में से 400 चीन सक्रिय थे। इन विशाल बहुराष्ट्रीय निगमों में से कई का चीन के बाजार में प्रभुत्व कायम हो चुका था। बहुराष्ट्रीय निगमों की एक रणनीति यह रहती है कि वे किसी देश में या तो अपनी ही शाखा देशीय नाम से खोल देते हैं या फिर वे ज्वाइंट

कम्पनियों का निर्माण कर लेते हैं। अकेले शंघाई में 2003 तक पश्चिम और जापान की 98 ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां थी जिन्होंने अपने आपको स्थानीय के बतौर पंजीकृत करवाया था। 1990 से चीन के कुल निर्यात व व्यापार में विदेशी धन प्राप्त संस्थानों का हिस्सा 2001 तक क्रमशः निर्यात में बढ़कर 17.4 से 50.8 तथा कुल व्यापार में 12.6 से 50.1 हो गया है (तालिका-2 देखें)।

कुल मिलाकर, तीनों चरणों के आर्थिक सुधारों के जरिये चीन के पूंजीवादी पथगामियों ने चीन के समाज को राज्य नियंत्रित पूंजीवादी व्यवस्था से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा दिया है। इस प्रक्रिया में चीनी अर्थव्यवस्था का विश्व पूंजीवादी व्यवस्था से तीव्र गति से एकीकरण हुआ। इस एकीकरण की प्रक्रिया से चीन के पूंजीपति वर्ग के साथ वैश्विक पूंजीवाद ने विशाल लाभ हासिल किये और इस प्रक्रिया की कीमत सीधे तौर पर चीनी सर्वहारा व अन्य मेहनतकश वर्ग ने चुकायी है तो अप्रत्यक्ष तौर पर चीन के निकटवर्ती देशों के सर्वहारा व मेहनतकश वर्ग के साथ दुनिया का सर्वहारा व अन्य मेहनतकश चुका रहा है।

दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स के मजदूरों को अपने शासकों की आर्थिक नीतियों के कारण अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया से LG, सैमसंग जैसी कई कम्पनियों ने अपने प्लांट चीन में बड़े लाभ पाने के लिए स्थानान्तरित किये हैं, इससे दक्षिण कोरिया में मजदूरों को छंटनी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यही प्रवृत्ति एक हद तक जापान व अन्य साम्राज्यवादी देशों से भी परिलक्षित हो रही है। जाहिर सी बात है कि इन देशों के पूंजीपतियों के अपने हित हैं तो चीनी पूंजीपतियों के अपने। लेकिन इनके लाभों की कीमत चीन तथा इन देशों के सर्वहारा चुका रहे हैं। वैश्विक पूंजीवाद की नीतियां सभी देशों के सर्वहारा पर कहर बनकर टूट रही हैं।

देंङ श्याओ पिंङ के बाद पार्टी का नेतृत्व संभालने वाले जियांङ जेमिन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता पूंजीपति वर्ग और धनी किसानों के सदस्यों के लिए भी खोल दी थी। जियांङ जेमिन ने तीन प्रतिनिधित्व' का सिद्धान्त दिया जो कि चीनी संविधान का हिस्सा बन गया है। जियांग जेमिन का 'तीन प्रतिनिधित्व' का सिद्धान्त कहता है कि पार्टी (I) चीन की उन्नत उत्पादक शक्तियों के विकास (II) चीन की उन्नत संस्कृति की दिशा तथा (III) चीन की समूची जनता के बुनियादी हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

यह सिद्धान्त ख्रुश्चेव के संशोधनवादी सिद्धांत कि 'सोवियत संघ की पार्टी समूची जनता की पार्टी है' और 'सोवियत संघ का राज्य समूची जनता का राज्य' का ही एक रूप है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता धनिकों के लिए खोलते हुए जियांङ जेमिन ने कहा कि 'किसी व्यक्ति की राजनीतिक दिशा का निर्धारण करते समय इस बात को आधार नहीं बनाना चाहिए कि वह सम्पत्ति रखता है या रखती है और कितनी सम्पत्ति वह रखता या रखती है। इसके बजाय उसका निर्धारण मुख्यतः इस बात से होना चाहिये कि उसका या उसकी राजनैतिक जागरूकता, नैतिक ईमानदारी और प्रगति कैसी है...'। जाहिर सी बात है अपने वर्ग के अनुरूप ही जियांङ जेमिन, हू जिनताओ समाज में अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। और यह विचारधारा निजी सम्पत्तिधारी वर्ग की विचारधारा है। संविधान में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा देंङ विचार और तीन प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दर्ज करने के साथ चीन के शासक अक्सर ही कन्फ्यूशियस और उसके नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। इस तरह विचारों के स्तर पर लम्बे-चौड़े उपसर्गों के बावजूद इस विचारधारा का सर्वहारा वर्ग या उसकी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। बुर्जुआ विचारधारा को सर्वहारा शब्दावली की आड़ में अब तक छुपाया जा रहा है। आज भी चीनी शासक आर्थिक सुधारों की तर्ज पर ही अपने वर्ग के हितों के अनुरूप राजनैतिक सुधार कर रहे हैं। चीन के पूंजीपति वर्ग ने न केवल अपनी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी बना कर रखा हुआ है बल्कि शासन प्रणाली का रूप भी पुराना ही बनाकर रखा हुआ है। पार्टी का नाम और शासन प्रणाली का रूप बदलने का साहस अभी चीनी पूंजीपति वर्ग के पास नहीं है।

चीनी समाज को लेकर आज तीन विश्लेषण प्रचलित हैं। चीन को अभी भी समाजवादी देश मानने वाली एक धारा है। इस धारा में दुनिया के तमाम संशोधनवादी, सामाजिक-जनवादी शामिल हैं। यह धारा समाजवाद के सवाल को महज सम्पत्ति के रूपों से जोड़ती है। यह धारा वही है जो 1990 तक सोवियत संघ को समाजवादी देश मानती रही है। यह धारा समाजवाद के सवाल पर स्थापित मार्क्सवादी-लेनिनवादी समझदारी को धूमिल करती है तथा अपने देश सहित दुनिया भर के सर्वहारा की आंखों में धूल झोंकती है। भारत में, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) इसका प्रतिनिधित्व करती है।

एक विश्लेषण प्रसिद्ध लेखक विलियम हिंटन ने प्रस्तुत किया है। विलियन हिंटन के अनुसार चीन पुनः एक अर्द्ध सामंती अर्द्धऔपनिवेशिक देश बन गया है। विलियम हिंटन के विश्लेषण को दुनिया के कई माओवादी स्वीकार कर सकते

हैं परन्तु यह विश्लेषण चीन के वस्तुगत यथार्थ से मेल नहीं खाता है तथा माओ की अर्द्ध सामंती-अर्द्ध औपनिवेशिक थीसिस से कोसों दूर खड़ा है।

एक अन्य विश्लेषण जर्मनी की मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी MCPD का है जो कि सांस्कृतिक क्रांति के महत्व को स्वीकारती है। इस पार्टी के अनुसार चीन एक सामाजिक-साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो चुका है। चीन को एक सामाजिक-साम्राज्यवादी देश मानने के पीछे उनकी दलील है कि चीन एक आर्थिक व सामरिक शक्ति बन चुका है और उसकी कम्पनियां पेरू, वेनेजुएला जैसे देशों में मार कर रही हैं व इन देशों के सर्वहारा के शोषण को अंजाम दे रही हैं और चीन के शासक पाकिस्तान में प्रतिक्रियावादी शासक मुशर्रफ का समर्थन कर रहे हैं।

हमारा मानना है कि चीन एक स्वतंत्र पूंजीवादी देश है जो कि साम्राज्यवाद के साथ आर्थिक नव औपनिवेशिक सम्बंधों में बंधा हुआ है। चीन एक विस्तारवादी देश है परन्तु साम्राज्यवादी मुल्क में तब्दील नहीं हुआ है। यह बात ठीक है कि कतिपय चीनी कम्पनियां विशेषकर चीन की तेल कम्पनियां पेरू, वेनेजुएला, बोलीविया, सऊदी अरब जैसे देशों में मार कर रही हैं। तब भी चीन एक विस्तारवादी देश है न कि एक साम्राज्यवादी मुल्क।

चीन के पूंजीवादीकरण ने चीनी समाज को एक गहरे अंधकूप में धकेल दिया है। चीन पूंजीवादी समाज में पायी जाने वाली सभी बीमारियों का शिकार हो चुका है। गरीबी, बेरोजगारी, गरीब व अमीर में बढ़ती खाई, क्षेत्रीय असमानता व असंतुलन, देहात व शहर में बढ़ता अंतर, मंहगाई, अति उत्पादन, महिलाओं में बढ़ता कुपोषण व भ्रूण हत्याएं, व्यापार व बजट घाटा पर्यावरण संकट इत्यादि सभी किस्म की पूंजीवाद जनित समस्याओं ने चीनी समाज को घेर लिया है। साम्राज्यवाद के साथ चीनी शासकों की जुगलबंदी ने इन समस्याओं को और गहरा दिया है। साम्राज्यवादी संस्कृति व विचारों ने चीनी समाज में अपनी पैठ बना ली। सामंती व दास समाज के तमाम कुत्सित विचारों व संस्कृति को समाज में फैलाया जा रहा है।

चीनी सरकार का रक्षा बजट प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। दुनिया में चीन बड़ी सैनिक शक्तियों में एक बनता है। इसके पास 25 लाख से अधिक सैनिकों वाली फौज है। अन्तरमहाद्वीपीय मिसाइलों के साथ चीन के पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। एक अनुमान के अनुसार चीन के पास 400 से अधिक परमाणु हथियारों से युक्त मिसाइलें हैं। चीन का बढ़ता रक्षा बजट और उसकी विशाल फौज चीनी शासकों की बढ़ती महत्वाकांक्षा तथा बढ़ते प्रतिक्रियावादी चरित्र की अभिव्यक्ति हैं। आज इस फौज का इस्तेमाल माओ कालीन समय के विपरीत मजदूरों और किसानों के संघर्षों का दमन करने के लिए अक्सर ही होता है। इस फौज का मेहनतकश जनता से अलगाव है।

कुछ उप शीर्षकों के तहत हम चीन की प्रमुख समस्याओं की आगे चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि चीन के आज के शासकों को दीवार पर लिखी गयी इबारत नहीं दिखायी दे रही है। उन्हें दिखायी दे रही है परन्तु हमेशा की तरह यह शोषक वर्ग भी पूंजीवाद के दायरे में इन समस्याओं का समाधान खोज रहा है जबकि वह स्वयं इनकी जड़ में है। इतिहास के हर शोषक वर्ग की तरह यह भी अपना स्थान अपने आप नहीं छोड़ेगा।

कुछ समय पूर्व चीन की सरकार ने भावी पंचवर्षीय योजना के लिए दस प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करवाया। 'ये दस समस्यायें थीं- बेरोजगारी, कृषि का गहराता संकट, मुद्रा प्रवाह से वित्तीय क्षेत्र का नकारात्मक ढंग से प्रभावित होना, अमीर व गरीब के बीच बढ़ते अंतर का अंतर्राष्ट्रीय लाल रेखा को पार करना, पर्यावरण समस्या, ताइवान संकट, वैश्वीकरण, विदेशी निवेश की उच्च दर से पैदा होने वाली अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, सरकार पर विश्वास और उसकी साख पर भ्रष्टाचार की छाया, एड्स और जन स्वास्थ्य।' (स्रोतः E P W, 9 Oct 2004)।

कृषि के गहराते संकट ने तो चीन के नये नेतृत्व को कृषि पर पुनः जोर देने को बाध्य कर दिया है जिसे कुछ धूर्त विश्लेषकों ने माओवादी काल की ओर की ओर लौटना कहा।

अमीरी व गरीबी के बीच बढ़ता अंतरः देंङ श्याओ पिंङ ने अपने शासनकाल के दौरान एक जुमला उछाला था कि 'कुछ लोग पहले अमीर' बन जायेंगे। और शीघ्र ही कुछ लोग-चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता, राज्य में बैठे पदाधिकारी, अफसर, सेना के अफसर, सार्वजनिक उद्योगों के मैनेजर, तेजी से फल-फूल रहे निजी उद्यमों के मालिक, दूसरों की जमीन हथिया रहे भूस्वामी, व्यापारी इत्यादि तेजी से अमीर बन गये। कई जो एक जमाने में चीन को छोड़कर अमेरिका, ताइवान, हॉङ-कॉङ आदि जगह चले गये थे, ऐसे अप्रवासी चीनियों (N R C) ने चीन में भारी निवेश किया और आज वे अरबों डालर बटोर रहे हैं।

ऊपर गिनाये गये लोग जहां तेजी से अमीर बनते गये तो उनके पीछे लाखों-करोड़ों थे जिनसे इस पूंजीवाद ने सब कुछ छीन लिया। मजदूरों से उनका "भात का लोहे का डोंगा" (iron rice bowl) छीन लिया गया। देहातों में भुखमरी, बेरोजगारी से जूझने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है।

समाज में असमानता को प्रदर्शित करने का एक अच्छा सूचक गिनी गुणांक (Gini coefficient) है। [गिनी गुंणाक 0 से 1 के बीच अपने मान प्रदर्शित करता है। 0 जहां निरपेक्ष बराबरी को प्रदर्शित करता है वहां 1 निरपेक्ष (absolute) गैर बराबरी को प्रदर्शित करता है।] मार्टिन हार्ट, लैण्ड्सबर्ग और पाल बर्केट के अनुसार :

" सुधार प्रक्रिया ने आय असमानता को बद से बदतर किया है। चीन में पारिवारिक आय के लिए गिनी गुणांक 1980 में 0.33 था, जो कि 1994 में 0.40 तथा 2000 में 0.46 हो गया। अंतिम संख्या असमानता के मामले में थाइलैण्ड, भारत और इण्डोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। कई पर्यवेक्षकों को आंशका है कि चीन में गिनी गुणांक 0.50 तक पहुंच गया है जो कि आय की असमानता के मामले में उसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ रख देता है।" (Analytical Monthly Review, July-Aug -2004, Page No-58, अनुवाद हमारा)

गिनी गुंणाक साफ तौर पर दिखला रहा है कि चीन में आय में असमानता बढ़ रही है। इसी प्रक्रिया की एक अन्य अभिव्यक्ति चीनी समाज में तीव्र गति से हो रहा वर्गीय विभाजन और ध्रुवीकरण है।

शहर और देहात के बीच बढ़ता अंतर :समाजवादी काल में माओ ने शहर और देहात के अंतर को कम करने के लिए लगातार नीतियां बनाने की कोशिशें की और इस अंतर को एक सीमा के भीतर रखा।

पूंजीवादी पुनर्स्थापना के साथ यह अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है। शहरों और देहात के जीवन में आय सहित तमाम किस्म की सुविधाओं के बीच अंतर गहराता जा रहा है।

सुधारों के पहले वर्ष में शहरी और ग्रामीण प्रति परिवार की आय क्रमशः 343.4 युआन तथा 133.6 युआन थी। 1995 में यह आय क्रमशः 4283.0 तथा 1577.7 युआन हो गयी और 2003 आते-आते यह क्रमशः 8472 व 2,622 हो गयी। 1978 में जहां शहरी व ग्रामीण आय में अनुपात 2.5 : 1 का था वहां 2003 में यह अनुपात 3.23 : । का हो गया। (तालिका -3 देखें)

शहर और देहात का अन्तर अपने आपको उद्योग और कृषि के अंतर के रूप में भी अभिव्यक्त करता है। चीन में कृषि और उद्योग के विकास में अंतर बढ़ता जा रहा है।

मार्टिन और पॉल के अनुसार :

" ... कम्यून व्यवस्था के नष्ट होने से तथा कृषि उत्पादन में (जो कि अस्सी के दशक के मध्य से ठहराव ग्रस्त होने लगे थे) कृषि आगतों (Inputs) के मूल्यों में वृद्धि ने हालत खराब कर दी है। कृषि आय जो कि 1978 - 84 के दौरान प्रतिवर्ष 15 % की दर से बढ़ रही थी वह 1985-88 में केवल 5% से तथा 1989 - 91 में सिर्फ 2% की वार्षिक दर से बढ़ रही थी। ग्रामीण उद्योग के निर्गत उत्पाद जो सालाना 37.7 % की दर से बढ़ रहे थे, मुद्रास्फीति और सरकार की नीतियों के शहरी उद्योगों के पक्ष में झुक जाने से हाल के वर्षों में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। (पृष्ठ - 40, वही, अनुवाद हमारा)

बेरोजगारी : समाजवादी काल में चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। "सुधारों" की गति बढ़ने और सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को छीनते जाने के साथ बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती चली गयी। देहातों में कृषि समस्या के साथ व्यापक पैमाने पर शहरों की ओर पलायन ने शहरों में बेरोजगारी की समस्या को और अधिक तीव्र किया है।

शहरी क्षेत्र में चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही बेरोजगारी की दर में निरंतर वृद्धि हुयी है। यहां उद्धृत की गयी तालिका (तालिका -4) को देखने से पता चलता है कि 1985 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 1.8% थी जो कि निरंतर बढ़ते हुए 2002 में 40 % हो गयी। 1985 से 2002 के बीच एक-दो वर्ष ही ऐसे हैं जब बेरोजगारी की दर स्थिर रही है।

चीन के सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी की दर को नीचा रखने के लिए कई प्रकार की बाजीगरी की जाती है। वास्तव में चीन में बेरोजगारी की दर का वास्तविक आकलन सरकारी दर के दूने से भी अधिक का है (देखें तालिका-5)। यह आकलन हॉगकॉग के एक संस्थान 'दि सोशल एण्ड इकोनामिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट' का है। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार विगत शताब्दी के नब्बे के दशक के मध्य में बेरोजगारी कामगार आबादी की आठ फीसदी हो चुकी थी।

मजदूरों की उजरती गुलामों में तब्दीली :समाजवादी काल में मजदूरों को 'भात के लोहे के डोंगे' के मुहावरे के तहत कई अधिकार और सुविधायें हासिल थीं। हर बालिग को काम मिलता था। समाजवादी काल में चीन में बेरोजगारी नहीं थी। सरकारी संस्थान में काम मिलने के बाद व्यक्ति को न्यूनतम दर पर आवास, निःशुल्क चिकित्सा, गर्भावस्था के दौरान सुरक्षा व इलाज, कामगार क्षतिपूर्ति, बीमा व पेंशन के साथ शिक्षा व मनोरंजन की सुविधायें हासिल थीं। राबर्ट वाइल ने ठीक ही लिखा है कि

"ऐसे में" "भात का लोहे का डोंगा" केवल काम की सुरक्षा या एक आर्थिक व्यवस्था का सूचक न होकर, समाजवाद का एक रूप है जो कि समाज को अपने वर्गीय सम्बन्धों एवं समानता पर आधारित रिश्तों के साथ समग्रता में संगठित किये हुए है।" (Robert, Weil, China at The Brink :Class contradictions of Market Socialism" MR, Dec. 1994, अनुवाद हमारा, page -29)

सुधारों के प्रारंभिक वर्षों में चीन के शासकों को मजदूरों से 'भात के लोहे के डोंगे' को छीनने की हिम्मत नहीं हुयी परन्तु बाद में उसने अपने मंसूबे बांध लिए थे। नब्बे के दशक में थोड़े से सरकारी उपक्रमों का छोड़ कर (जहां के मजदूर चीनी समाज के अभिजात मजदूर बन गये हैं और आर्थिक सुधारों के समर्थक हैं) अधिकांश मजदूर आबादी से 'भात से भरे लोहे के डोंगे' को छीन लिया गया। लाखों की संख्या में मजदूरों को गरीबी, बेरोजगारी के भंवर में धकेल दिया गया।

सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के फलस्वरूप इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की स्थिति गम्भीर होती जा रही है। मार्टिन और पॉल ने इस स्थिति का वर्णन इस तरह किया है।

" राजकीय क्षेत्र को विघटित करने से बेरोजगारी की समस्या गहराती जा रही है। राज्य के मालिकाने वाले उद्यमों की संख्या 1995 में लगभग 1,000,00 थी जो कि 1999 में घटकर लगभग 60,000 रह गयी। इस गिरावट ने भारी पैमाने पर राजकीय क्षेत्र के मजदूरों की छंटनी को जन्म दिया। उदाहरण के लिए, 1996 से 2001 के बीच राजकीय उद्यमों में से कुल मिलाकर 3 करोड़ 60 लाख मजदूरों की छंटनी की गयी, इसी समय सहकारी फार्मों से एक करोड़ सत्तर लाख मजदूरों की छंटनी की गई।

" इतने भारी पैमाने पर छंटनी के बाद सरकार दावा करती है कि शहरी क्षेत्रों में 1995 -2000 के बीच बेरोजगारी की दर केवल 2.9 से 3.1 प्रतिशत बढ़ी है।"(Martin & Paul, AMR July-August-2004, page-57, para-I&II)

तालिका - 3

शहरी तथा ग्रमीण आय में अंतर

वर्ष	प्रति शहरी परिवार की प्रयोज्य वार्षिक आय (युआन में)	प्रति ग्रामीण परिवार की कुल आय (युआन में)	शहरी व ग्रामीण आय का अनुपात
1978	343.4	133.6	2.5 %1
1980	477.6	191.3	2.50 %1
1985	739.1	397.6	1.86 %1
1990	1,510.20	686.3	2.20 :1
1991	1700.6	708.6	2.40 :1
1992	2026.6	784	2.58 :1
1993	2577.4	921.6	2.80 :1
1994	3496.2	1221	2.86 :1
1995	4283	1577.7	2.72 :1
1996	4838.9	1926.1	2.51 :1
1997	5160.3	2090.1	2.47 :1
1998	5425.1	2162	2.51 :1
1999	5854	2210.3	2.65 :1
2000	6280	2,253.40	2.79 :1
2001	859.6	2,366.40	2.90 :1
2002	7700	2,476	3.11:1
2003	8472	2,622	3.23 :1

स्रोत: China Statistical Year Book, 'The Marxist' के अप्रैल-सितम्बर 2005,पृष्ठ-77

मार्टिन व पॉल के अनुसार सरकारी आंकड़े स्थिति का सही आकलन नहीं करते। चीन में बेरोजगारी की दर को नीचा रखने का नायाब तरीका निकाला हुआ है। जिन मजदूरों की राजकीय उद्यमों से छंटनी कर दी जाती है उन्हें बेरोजगार नहीं माना जाता है और सरकारी आंकड़ों में उन्हें बन्द हो चुके उद्यमों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है इसी तरह एक अन्य तरीके के जरिये उन 50 वर्ष की उम्र से कम के पुरुषों और 45 वर्ष से कम की स्त्रियों को ही बेरोजगार माना जाता है जो कि काम से निकाल दिये गये हैं। यह है 'चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद' की बाजीगरी। इस तरह झूठे आंकड़े तैयार करके आम जनता की आंखों में धूल झोंकी जाती है।

तालिका -4

चीन में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी

वर्ष	उपभोक्ता मूल्यों में सालाना मुद्रास्फीति (%)	शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर (%)
1985	9.3	1.8
1986	6.5	2
1987	7.3	2
1988	18.8	2.6
1989	18	2.5
1990	3.1	2.3
1991	3.4	2.3
1992	6.4	2.6
1993	14.7	2.8
1994	24.1	2.9
1995	17.1	3
1996	8.3	3.1
1997	2.8	3.1
1998	-0.8	3.1
1999	-1.4	3.1
2000	0.3	3.1
2001	0.9	3.6
2002	-0.8	4

स्रोत :**Table-7,China Statistical Year book, 2002,(Analytical Monthly Review, July-Aug 2004)**

तालिका -5

शहरी इलाकों में बेरोजगारी: सरकारी बनाम वास्तविक आकलित दर

वर्ष	सरकारी दर (%)	वास्तविक आकलित दर (%)
1993	2.6	3.3-3.7
1994	2.8	3.6-4.1
1995	2.9	4.4-5.0
1996	3	5.1-6.0
1997	3.1	6.8-7.8
1998	3.1	7.9-8.3

स्रोत : **Social and Economic Policy Institute, (AMR July-Aug 2004, Table - 8)**

प्रवासी (Migrant) मजदूरों की स्थिति चीन में बहुत खराब है। इन मजदूरों में देहात के उजड़े और बर्बाद हुए किसान बहुतायत में शामिल हैं। इन्हें न तो कोई सामाजिक सुरक्षा है और न ही इन्हें शहरों और देहातों में नागरिक अधिकार हासिल हैं। ये आबादी लगातार काम की तलाश में इधर-उधर भटकती रहती है और सबसे बुरी परिस्थितियों में काम करने व रहने को मजबूर है। आज चीन के हर शहर ऐसे 'घेट्टो' तैयार हो गये हैं जहां ये मजदूर नागरिक अधिकारों से विहीन हो कर रह रहे हैं। इनमें महिला मजदूरों की हालत और भी खराब है।

राबर्ट बाइल ने अपने लेख 'Condition's of the Working class in China' में प्रवासी मजदूरों की हालत का वर्णन किया है। यह वर्णन आज के चीन की परिस्थितियों का बड़ा खुलासा है। रावर्ट बाइल लिखते हैं :

" अब जो बात स्पष्ट है वो यह कि प्रवासी कामगार शक्ति को चीन में मुख्य मजदूरों और किसानों की परिधि पर लम्बे समय तक रखा जा सकता है। अकेले बीझिंङ शहर में, जिसकी आबादी करीब डेढ़ करोड़ है, में तीस लाख प्रवासी मजदूर हैं। ...

"... ये प्रति हफ्ते 70 से 80 घंटे काम करते हैं ... ये विभिन्न किस्म के घटिया कामों को करते हैं जिसे कोई शहरी चीनी नहीं करना चाहेगा ... इसके लिए ये प्रतिमाह 500 से 900 यूआन हासिल करते हैं ...

इनका शोषण न केवल अत्यधिक है बल्कि ये बहुत ही बुरी परिस्थितियों में रहते हैं ... कुछ प्रवासी मजदूरों ने आखिरी कदम उठाते हुए निर्माण स्थल में कार्यरत क्रेनों में फांसी लगा ली ... । ये चीनी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक 'श्रमिकों की रिजर्व सेना' का प्रतिनिधित्व करते हैं।

"... गावों को छोड़कर जब ये शहरों में आते हैं तो ये "चार नहीं": परिवार नहीं, भविष्य नहीं, पुत्र नहीं, बेटी नहीं का सामना करते हैं। " (अनुवाद हमारा, स्रोत: www.monthlyreview.org)

चीनी सरकार तो सामाजिक कार्यों से हाथ खींचती जा रही है। सामाजिक कार्यों के लिए वह गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित कर रही है। और इसी के तहत उसने प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी इन गैर सरकारी संगठनों पर छोड़ दी है। फोर्ड फाउण्डेशन ने ऐसे कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए दस लाख डालर का फंड दिया है। पूंजीवाद द्वारा पैदा किये जा रहे जख्मों के लिए यह मरहम पट्टी ऐसी है कि यह सिर्फ जख्मों को छुपा भर सकती है। पूंजीवाद अपने साथ कैसे मानवतावादी, सुधारवादी, परोपकारी संस्थाओं को लेकर आता है ये नये उभरते हुए गैर सरकारी संगठन इसकी एक अभिव्यक्ति हैं।

चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी उच्च विकास दर दुनिया के सभी पूंजीवादी देशों के लिए मॉडल है। अमेरिका से लेकर भारत तक चीन के आर्थिक सुधारों के जरिये हासिल किये गये लाभों के कायल हैं। आर्थिक सुधारों से फायदा पार्टी और राजसत्ता में बैठे पदाधिकारियों व नेताओं, नौकरशाह व निजी पूंजीपतियों और उनके बेटे-बेटियों तथा रिश्तेदारों को हुआ। लाभ के भागीदार विदेशी पूंजीपति भी बने परन्तु मजदूरों की परिस्थितियां बद से बदतर होती गयीं और वे अपने खून-पसीने से इसकी कीमत चुका रहे हैं।

चीन में बुरी हुयी कार्यपरिस्थितियों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। राबर्ट वाइल ने 1994 -95 में अपने लेख में इन दुर्घटनाओं व उनके कारणों का वर्णन इस प्रकार किया है :

"....दूसरी तरफ मुनाफा बढ़ाने को प्रोत्साहन और विशेषकर विदेशी निवेशकों व साझे उद्यमों को दिये गये "विशेष अधिकारों" का परिणाम मजदूर वर्ग के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। ग्वांङदोंङ प्रांत में शेनझेन नामक सबसे पहले स्थापित हुए विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र' में 19 नवम्बर 1993 के दिन झिली खिलौना फैक्टरी में आग लग गयी। इस कुख्यात अग्निकाण्ड में "मजदूरों को चोरी से रोकने के लिए बनाये गये एक पिंजड़ा रूपी कारखाने में" 81 मजदूर बंद दरवाजों के पीछे फंसकर मारे गये। अन्य 42 मजदूर घायल हुए। अग्निकाण्ड ने न्यूयार्क में 82 वर्ष पूर्व हुए इस तरह के एक दर्दनाक हादसे की याद ताजा कर दी (चाइना डेली, 22 नवम्बर 2003, पृष्ठ 3) ... झिली काण्ड ने चीन में पनप रहे मजदूरों का खून चूसने वाले कारखानों की पोल खोल दी। इसमें मानवीय शोषण के एक सुव्यवस्थित तंत्र व कारखाने की खतरनाक परिस्थितियों का पर्दाफाश हो गया। ...

दरअसल झिली अपने क्षेत्र का एक सामान्य कारखाना है, जहां पहले ही फैक्टरी के नियमों के उल्लंघन की बात उजागर हुई थी। लेकिन मालिक व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से कानून लागू नहीं हो सके थे। वहां का अग्निकाण्ड समूचे शेनझेन की पीड़ा-व्यथा की एक झलक मात्र है, वर्ष 1992 में ग्वांङदोंङ प्रांत भर में औद्योगिक हादसों में मरने वालों की तादाद 836 तक जा पहुंची थी। एक साल के भीतर उस तादाद में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। उधर चीन भर में उस वर्ष 15,000 मजदूर औद्योगिक हादसों में मर चुके थे। 1991 की तुलना में यह तादाद सिर्फ 3.3 प्रतिशत ज्यादा थी। इसके बाद 1993 के प्रारम्भिक महीनों में एक के बाद एक कई हादसे हुए, जो अखबारों के मुताबिक "भयानक वृद्धि" थी। 1993 में जनवरी से अक्टूबर के बीच 60,000 मजदूर हादसों में मारे गये। जहां पहले "हादसे ज्यादातर विदेशी पैसों वाली कम्पनियों व सरकारी कम्पनियों की खदानों में होते थे" "वहां अब राजकीय उद्यमों में भी वही स्थिति सामने आने लगी।" (Robert Weil, MR Dec. 94 व Jan. 1995, अनुवाद समाजवादी विवेचना, अंक-5)

चीन के एक सरकारी विभाग के अनुसार दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2001 में ऐसी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या जहां 1,00,000 दर्ज की गयी वहां यह 2002 में बढ़कर 1,40,000 हो गयी। गम्भीर ढंग से घायल मजदूरों की संख्या इससे कहीं अधिक है। जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चीन का कोयला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारी संख्या में दुर्घटनायें होती हैं। चीन में कोयला खनन में होने वाली दुघर्टनाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। फ्रंटलाइन में छपे एक लेख ('Price of growth' by Pallavi Aiyyar-Frontline 19 May, 2006) के अनुसार चीन के कोयला खनन में होने वाली 70 फीसदी दुघर्टनायें निजी क्षेत्र में होती हैं। 2003 में 6,343 मजदूरों की मृत्यु हुई जिसमें 1,773 सरकारी क्षेत्र में हुई। निजी क्षेत्र के कई कोयला कम्पनियों के मालिक या तो स्थानीय पीपुल्स कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं या फिर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी हैं।

चीन में मजदूरों को स्वतंत्र यूनियन बनाने व हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। इसके चलते मजदूरों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। एक ही यूनियन आल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (ACFTU) है जो कि

सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस यूनियन में भी सरकार और सुधार समर्थक अभिजात मजदूरों और उनके नेताओं का वर्चस्व है। आज यह यूनियन मई दिवस पर मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के स्थान पर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को सम्मानित करती है और उन्हें पदक प्रदान करती है।

राबर्ट वाइल ने अपने एक लेख में इन हालतों की चर्चा इन शब्दों में की है :

"... इस तरह के अधिकांश संघर्षों में "सरकारी" मजदूर यूनियन अब बेकार हो चुकी हैं, वास्तव में ये सक्रिय रूप से प्रबंधन और अधिकारियों (authorities) की सहायता करती हैं। सामान्य तौर पर मजदूरों को समझौते करने, इस बात के लिए कि धीमे-धीमे मजदूरों की छंटनी हो या फिर उपकरणों को बेचने के लिए चाल गढ़ने पर इनके नेताओं को धन दिया जाता है। फैक्टरी में "लोगों के प्रतिनिधियों" द्वारा सब कुछ की मजदूरों से चर्चा नहीं की जाती है। इसके बजाय जिन मजदूरों से हम मिले उनमें से एक ने इस बात को इस तरह रखा कि वे हमारे "भविष्य और जीवन को बेच रहे हैं"। यह कोई माओ का युग नहीं है जब यूनियनों के नेता मजदूरों के वास्तविक प्रतिनिधि होते थे और उनका चुनाव होता था। जब से "सुधार" प्रारम्भ हुये हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है और मजदूरों व कार्यकर्ताओं को विभाजित करने के लिए वेतन तथा रोजगार का इस्तेमाल किया जाता है। यूनियनें "बाजार अर्थव्यवस्था" तंत्र का बस एक हिस्सा हो गयी हैं। " यहां यूनियनें मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं बल्कि वे उन्हें बेचती हैं"। मजदूर उन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जो अधिकारी कहते हैं-"वे धोखा देते हैं"। और जो कोई वास्तविक यूनियन बनाना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।" (Robert weil, Conditions of the working class in China, 2005, हिन्दी अनुवाद हमारा, स्रोत : www.monthlyreview.org)

तबाह होते किसान :मजदूरों के बाद चीन के "विकास" की कीमत किसान चुका रहे हैं। चीन के देहात में रहने वाली आबादी की संख्या 80 करोड़ से भी अधिक है। देंङ श्याओ पिंङ के "सुधारों" के केन्द्र मूलतः शहर रहे हैं। गांवों ने हर पूंजीवादी व्यवस्था की तरह चीन में भी महज अनदेखी और उपेक्षा पाई है। साथ ही हर पूंजीवादी व्यवस्था में जो बदहाली और तबाही मेहनतकशों की होती है वही किसानों की "सुधारों" के युग में हो रही है।

देंङ श्याओ पिंङ एक धूर्त पूंजीवादी नेता था। वह अच्छी तरह जानता था कि देहात में "सुधारों" को लागू करने के लिए किसानों के बीच तीव्र विभेदीकरण को जन्म देना होगा। इसके लिए "सुधारों" की प्रारम्भिक कोशिशों में कृषि कम्यून तोड़ दिये गये और किसानों के बीच पारिवारिक उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। 1982 में कानूनों में फेरबदल किये गये जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। "पारिवारिक उत्पादन प्रणाली" ने जैसे-जैसे कम्यूनों को स्थानांतरित किया वैसे-वैसे देहातों में वर्गीय ध्रुवीकरण तीव्र हो उठा। धनी किसानों के साथ-साथ मध्यम किसानों के उदय से एक बड़ी आबादी गरीबी, तबाही के दलदल में धकेली जाने लगी। इस ग्रामीण बेदखल आबादी का एक हिस्सा प्रवासी मजदूरों के रूप में प्रकट हो गया है। हालत कितने बुरे होते जा रहे थे इसका अनुमान चीनी सरकार के एक पुराने आंकड़े से लगाया जा सकता है। 1993 के चीनी सरकार के अनुमान के अनुसार 'देहात में कम से कम 10 करोड़ किसान "बेकार" हैं तथा 3 से 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा काम की तलाश में घूम रहे हैं, जिसमें 80 % युवा हैं।"

सन 2000 में भी चीन में कृषि क्षेत्र 50 फीसदी से अधिक रोजगार दिलाने वाला क्षेत्र था यानी बरबाद होती कृषि से तबाह हुये किसानों के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्थान नहीं के बराबर है। राबर्ट वाइल ने MR में 1994 -95 में छपे लेखों में किसानों की स्थिति की चर्चा करते हुए लिखा है,

" ... इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कुछ किसानों को निजी दौलत कितनी भी मिली हो, पूरी किसान आबादी निश्चित तौर पर त्रस्त है। और यह भी कि शहरों की आसमान छूती मुनाफाखोरी एवं बढ़ती खपत तथा ढांचा टूटने के कारण कम हुई आय की पूर्ति के लिए खेती के इलाकों की आय छीनी जा रही है। इसके अलावा इस घटनाक्रम का गंभीर परिणाम कृषि क्षेत्र को तकनोलाजी आधारित साधनों की आपूर्ति करने की व्यवस्था पर पड़ा है, जो अन्य क्षेत्रों की तरह अर्ध-निजीकृत हो चुकी है और अधिक लाभप्रद उद्यमों के सामने टिक न पाने के कारण बिखर रही है। उपरोक्त कारकों का प्रभाव एक ऐसी अर्थव्यवस्था में अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकता है जिस पर दुनिया की आबादी में से पांचवे हिस्से को खिलाने की जिम्मेदारी है और जिस देश की तीन चौथाई जनता अभी खेती ही कर रही है।" (अनुवाद-समाजवादी विवेचना, अंक - 5, फरवरी - 96)

पूंजीवादी व्यवस्था में आंकड़े कैसे तैयार किये जाते हैं। इससे हर मार्क्सवादी परिचित है। चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देहात में रहने वाली आबादी में से गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या कम हुई है। 1978 में गरीबी रेखा के नीचे 25 करोड़ आबादी (31.61 %) रह रही थी जो कि सन् 2000 में तीन करोड़ (3.7%) रह गयी थी और 2003 तक तो मात्र 2.9 करोड़ थी। सच्चाई कुछ और कह रही है।

" यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2002 में जेजियांग प्रान्त में 8.8 लाख किसानों ने अपनी जमीनें खो दी हैं ...

"... विभिन्न किस्म के विकास क्षेत्र 36000 वर्ग कि.मी. के खेती योग्य इलाके को छीन रहे हैं, जमीन से बेदखल किसानों की संख्या तीन करोड़ पचास लाख है जिसमें 50% भूमि विहीन और रोजगार विहीन हैं।" (Zhang Xiaoshan," Turning Government Priorities for Rural Devlopement in to Realities How ? " The Maxist AP, Sept . 2005)

" राष्ट्रव्यापी जनस्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा जो 1978 में 90 फीसदी था 1997 में गिर कर 4 % रह गया है।"

" अधिकांश देहात के निवासियों (जो कि आबादी का 65 फीसदी हैं) की आय पिछले चार वर्षों (1998 - 2001) से रुद्ध है। सन 2010 तक भूमिहीन किसानों की संख्या दस करोड़ से अधिक हो सकती है। (Paul &Martin, AMR July-Aug-2004)

" चीन की ग्रामीण कामगार आबादी सन् 2003 में 48.8 करोड़ थी जिसमें से 30 करोड़ अवरोजगार (underemployed) वाले थे। अनुमान लगाया गया है कि जिस अनुपात और सिलसिले के बतौर ग्रामीण कामगार शहरों में काम ढूंढ रहे हैं यह आबादी अगले दशक में 20 करोड़ पहुंच जायेगी। कम्युनिस्टों को सत्ता प्राप्त करने में किसानों और फार्मरों ने जैसे अति आवश्यक समर्थन दिया था वैसे ही प्रवासी मजदूर उसे सत्ताच्युत करने में भूमिका निभायेंगे।" (Migrant Workers in China , by - Chris Richards, www.newint.org/issue371)

कुल मिलाकर ये तथ्य यह बताते हैं कि चीन के देहातों में हालत कितने बुरे हैं और मेहनतकश किसानों का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी सर्वहारा में तब्दील हो रहा है। चीन का कृषि क्षेत्र जबरदस्त दबाव में है और उसमें विकास कमोबेश थम सा गया है। टाटा स्टेटिस्टिकल के 2005-06 के संस्करण के अनुसार चीन में कृषि क्षेत्र में 1980-90 के बीच प्रति वर्ष औसत वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत रही थी जो कि 1990-03 के बीच घटकर 3.5 रह गयी। चीन में बढ़ते कृषि संकट के कारण ही हू-जिन ताओ कृषि पर पुनः ध्यान देने की बात करता है। यद्यपि उसके ध्यान देने का अर्थ है कि 'सुधारों' का मुख्य जोर जो अब तक उद्योग और शहरों में रहा है उसका लक्ष्य अब कृषि और देहात होने चाहिये। ये पाखण्डी समाजवाद काल के नारे 'उद्योग की नेतृत्वकारी भूमिका और कृषि को आधार बनाओ' को इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते हैं।

तरह-तरह की चारदीवारियां :एक समुदाय के बतौर महिलाओं को पूंजीवादी पुनर्स्थापना के कारण बहुत ही कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। एक तरफ उनको पुनः कन्फ्यूशियसवादी विचारों से जीवन जीने के तरीके सिखाये जा रहे हैं तो दूसरी ओर पतित साम्राज्यवादी संस्कृति चीन के बड़े शहरों में फैशन परेड, 'मिस चाइना' जैसी सौन्दर्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रही है।

समाजवादी काल में जिन चीजों का या तो नामोनिशान मिटा दिया गया था या जो मिटने की ओर बढ़ रही थी अब पुनः प्रकट हो गयी हैं। वेश्यावृत्ति, कन्याभ्रूण हत्या, यौन अपराध, तलाक, महिलाओं से मारपीट, आदि पुनः प्रकट हो गये हैं और चीनी शासकों ने महिलाओं को पूंजीवादी नरक के दरवाजे पर ला खड़ा किया है।

महिला कामगारों को पूंजीवादी पुनर्स्थापना को मजबूत करने वाले "आर्थिक सुधारों" ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकारी उद्यमों (SOE's) में छंटनी किये गये मजदूरों में महिला मजदूरों की संख्या 60% है। यह तब जब कि महिलायें कामगार आबादी का मात्र 40 % हैं। आम तौर पर रोजगार मिलने में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक समय लगता है।

मार्टिन और पॉल ने महिला मजदूरों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है,

"जो महिलाएं काम कर रही हैं वे भी ऐसी जगहों (जैसे-चौकीदारी, सेवा कार्य, रेस्तरां इत्यादि में) में काम कर रही हैं जहां पर वेतन बहुत कम है तथा काम करने वाले बहुत अधिक। जबकि उद्योग और प्रबंधन में उच्च वेतन देने वाली नौकरियां पुरूषों के लिए आरक्षित हैं। यहां तक कि एक ही तरह की कार्य श्रेणियों में भी महिलाओं को कम वेतन दिया जाना प्रचलित है और पुरूष-महिला का वेतन अंतर (कार्य विशेषताओं को काबू करने के लिए) सरकारी उद्यमों (SOE's) के मुकाबले अधिक उदारीकृत संस्थानों (विदेशी सहायता प्राप्त) में अधिक है। जो मैन्यूफैक्चरिंग में काम करती हैं उनसे अक्सर श्रम संघनित जगह में तुच्छ वेतन में ... काम करवाया जाता है। " (Martin & Paul, AMR July-Aug 2004,अनुवाद हमारा)

राबर्ट वाइल ने 1995 में महिला कामगारों को वर्णन करते हुए लिखा,

" नौकरियों के लिए बढ़ रही प्रतियोगिता का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल औरतों के साथ गैर बराबरी के लिए किया जा रहा है। ...

"स्त्रियां, चीन की श्रम शक्ति का सर्वाधिक असुरक्षित व अंसगठित तबका हैं, क्योंकि पहले तो वे अपने घरों से हजारों मील दूर, अपरिचित शहरी परिवेश में रह रही हैं। आमतौर पर अशिक्षित इन स्त्रियों का न्यूनतम सामाजिक सहूलियतों व सुरक्षा के प्रति सचेत न होना सामान्य बात है। बुजुर्ग आदमियों के प्रभुत्व वाले समाज में ये युवा नारियां अपने को विशेष रूप से अशक्त और हैसियत-विहीन पाती हैं। उनमें से कइयों की नियति सड़कों पर वेश्यावृत्ति या अश्लील धंधों के शिकार बनने की होती है। 1993 में ग्वांङदोंङ में एक छापे के दौरान लगभग 33,000 वेश्याएं गिरफ्तार हुईं। (पेज 39, अनुवाद स. विवेचना, फरवरी 96)

वास्तव में, महिला मजदूरों को 'निर्यात क्षेत्रों में बहुत ही बुरी परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। अक्सर ही उन्हें फैक्टरी के साथ लगे दड़बेनुमा घरों में रखा जाता है जहां पर स्वच्छ हवा से लेकर पर्याप्त शौच सुविधा तक का अभाव होता है। बिमार, गर्भवती तथा प्रौढ़ व उम्रदराज होने पर उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण व सामाजिक असुरक्षा के दल-दल में धकेल दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा से विहीन ये महिला कामगार अभिशप्त जीवन जीने को विवश कर दी गयी हैं।

गांवों में भी स्थिति कम बुरी नहीं है। कम्यून व्यवस्था के टूटने और निजी भूमि व्यवस्था के प्रारम्भ होने से महिलायें बिल्कुल अधिकार विहीन हो गयी हैं। पुत्र को जमीन हस्तांतरित करने की भावना के जोर पकड़ने से कन्या भ्रूण हत्यायें तेजी से बढ़ रही हैं। एक ही सन्तान की नीति के कारण गांवों में पुत्रों की पैदाइश पर जोर अधिक है। लारल बोसन ने हाल में अपने एक लेख (**Forty Million Missing Girls :Land, Population Control and Sex Imbalance in Rural China, 7 Oct , 2005, Internet**) में इस समस्या की भयावह तस्वीर खींची है। इस लेख में कहा गया है कि चीन में 4 करोड़ लड़कियां गुम हो गयी हैं। गुमशुदा इन लड़कियों में अधिकांश वो है जिन्हें गर्भ में ही मार डाला गया है।

V

वर्ग संघर्ष की स्थिति

मजदूरों, किसानों, स्त्रियों की बुरी हालत जहां चीनी पूंजीवादी समाज की तस्वीर के एक पहलू को दिखा रही है वहीं मजदूरों, किसानों, छात्रों के बीच बढ़ता असन्तोष व क्षोभ समय-समय पर फूटने वाले आंदोलन व जन प्रदर्शन के रूप में दूसरा पहलू सामने आ रहा है।

चीन में पूंजीवादी पुनर्स्थापना के बाद लागू किये गये सुधारों के पूरे दौर में आक्रोश फूटता रहा है। सुधारों के प्रथम चरण में ही मजदूरों, विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के बीच बढ़ते अंसतोष तथा शासकों के जनविरोधी रवैये के खिलाफ छोटे-बड़े आंदोलन तथा संघर्ष के विभिन्न रूप प्रकट होने लगे थे।

1979 में 'डेमोक्रेसी वाल मूवमेंट' (**Democracy Wall Movement**) पैदा हुआ जो कि किसी न किसी रूप में 1981 तक चलता रहा। सुधारों के काल में पूंजीवादी पथगामी शासकों के बढ़ते फासीवादी रुझान व सुधारों के खिलाफ यह आंदोलन पैदा हुआ। देंङ श्याओ पिंङ ने शुरूआत में इस आंदोलन का इस्तेमाल सांस्कृतिक क्रांति के खिलाफ किया। बाद में जब उसे लगा कि यह आंदोलन उसकी नीतियों के खिलाफ जा रहा है तो उसने इसका क्रूरता पूर्वक दमन किया। इसके नेताओं को गिरफ्तार किया तथा प्रकाशन बंद करवा दिये गये। परंतु यह आंदोलन अपने भीतर कई तरह के रुझान लिये हुआ था। एक तरफ इसमें सांस्कृतिक क्रांति के दौरान के तौर-तरीके इस्तेमाल किये गये तो दूसरी तरफ इसमें शामिल कई लोग पश्चिमी बुर्जुआ लोकतंत्र से या फिर पोलैण्ड में लेक वालेसा के नेतृत्व में चले 'सालिडैरिटी यूनियन मूवमेंट' (**Soildarity Union Movement**) से प्रभावित थे। 'डेमोक्रेसी वाल मूवमेंट' के दौरान स्वतंत्र यूनियन बनाने के प्रयास किये गये, अवैध ग्रुप बनाये गये, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पर्चे प्रकाशित किये गये।

" चीन में 1980 के दशक के प्रारम्भ में स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक अंशाति फैलने की कई घटनायें घटी। इसमें 1981 में टाईयून आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में हुआ विवाद भी शामिल है।" (Martin &Poul, AMR, July Aug 2004, Page - 68)

जैसे पहले चर्चा की जा चुकी है कि 1980 तथा उसके बाद के वर्षों में कृषि कम्यून व्यवस्था को तोड़ा जा रहा था, विशेष आर्थिक जोन स्थापित किये जा रहे थे और 1982 में चीन के नये संविधान ने मजदूरों के हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

अस्सी के दशक में सुधारों की गति के तीव्र होने से पड़ने वाले प्रभाव तथा समाज में मेहनतकश वर्ग तथा छात्रों व बुद्धिजीवियों पर पूंजीवादी पथगामी शासकों के प्रतिक्रियावादी शासन के बढ़ते दबाव के खिलाफ असंतोष और मुखर होने लगा। छात्रों ने 'डेमोक्रेसी वाल मूवमेंट' की अगली कड़ी के रूप में 1989 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन छेड़ा।

अप्रैल 1989 में थियानमेन चौथ में छात्रों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने शुरू किये। दिनों-दिन छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती चली गयी। छात्रों के समर्थन में मजदूर भी बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी करने लगे। इस दौरान पहले पहल बीझिंङ में बाद में अन्य शहरों में मजदूरों के स्वायत्त संगठन पैदा होने लगे। बीझिंङ ऑटोनोमस वर्कर्स फेडरेशन (**Bejing Autonomous Worker's Federation**) की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई और इसकी सदस्य संख्या 20,000 तक जा पहुंची। चीन की पूंजीवादी सरकार ने इस आंदोलन को साम्राज्यवाद समर्थित कह कर कुचल डाला। सरकारी सेनाओं द्वारा व्यापक पैमाने पर हत्याओं और गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया। 2 जून को सरकारी ट्रेड यूनियन आल चाइनीज फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (**ACFTU**) ने मजदूरों के स्वायत्त संगठनों **(Autonomous Worker's Federations WAF 's)** पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, कि इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाय। दो दिन के भीतर सरकार ने इस संगठन के पूरे नेटवर्क को नष्ट कर दिया और इसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

नब्बे के दशक में स्वतंत्र मजदूर यूनियन बनाने के कई प्रयास किये गये। मार्टिन व पॉल के अनुसार " 1991 में बीझिंङ में **Free Trade Unions of China** का गठन हुआ। 1994 में बीझिंङ में ही **The League For the protection of the Rights of Working people** का गठन हुआ। 1994 में ही शेन जेन मे **Hired Hand Workers Federation** का गठन हुआ।"

सुधारों के काल में चीन में स्वतंत्र मजदूर यूनियनों का गठित होना एक बड़ी घटना रही है। यद्यपि ये यूनियनें अल्पजीवी साबित हुई हैं तथा लम्बे समय तक चीनी शासकों के दमन का सामना नहीं कर पायीं। इनका महत्व इस बात में भी है कि चीनी मजदूर सरकारी स्थापित ट्रेड यूनियन के दायरे को तोड़कर तथा उसे नकार कर अपनी स्वतंत्र यूनियनें गठित कर रहे हैं। सरकारी ट्रेड यूनियन का एक प्रमुख कार्य यही बन कर रह गया है कि वह चीनी शासकों के जनविरोधी सुधारों को श्रमिकों के बीच स्वीकार्य बनायें और देशी-विदेशी पूंजी के मार्ग को सुगम करें। हद तो यह होने लगी है कि अभी पिछले वर्ष 2005 में इस यूनियन ने पूंजीपतियों को मई दिवस के दिन सम्मानित किया और उन्हें मेडल बांटे।

नब्बे के दशक में अलग-अलग रिपोर्ट के अनुसार मजदूरों के संघर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। **ACFTU** के अनुसार 1995 में 25000 से अधिक हड़तालें हुईं और इनमें शामिल मजदूरों की संख्या 4,50,000 से अधिक थी।

नब्बे के दशक में सुधारों के चरण में मजदूरों के प्रतिरोध का वर्णन करते हुए ली मिन्की ने लिखा है,

> *"चीनी मजदूर वर्ग राजनैतिक हार से गुजरा है लेकिन अभी भी 'भात के लोहे के डोंगे की' "समस्या" पूरी तरह से हल नहीं हुई है। 1992 में शासक वर्ग ने "सुधारों" की नई श्रृंखला पेश की ताकि हर और हमेशा के लिए 'भात के लोहे के डोंगे' को तोड़ा जा सके। मजदूर वर्ग ने इसका जबर्दस्त प्रतिरोध किया। यह सूचित किया गया है कि कुछ घटनाओं में मजदूर हिंसक हो उठे और उन्होंने मैनेजरों और डायरेक्टरों की हत्या कर दी।" (L. Minqi, China : Six years After Tianmann, MR-Jan 1996 अनुवाद हमारा)*

मार्टिन और पॉल नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध के बारे में लिखते हैं-

> *" चीन के सरकारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन में मजदूरों का प्रतिरोध बढ़ रहा है। वर्ष 1999 में सरकार के अनुसार 1,98,000 श्रम विवाद हुये। यह संख्या 2000 में बढ़कर 3,27,152 हो गयी।*

इसमें प्रिंगल ने आगे जोड़ा,

> *" ये आंकड़े 1990 के दशक के शुरू से चले आ रहे विवादों की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाते हैं। क्योंकि इन श्रम विवादों में व्यक्तिगत श्रम विवाद भी शामिल हैं जिनका अक्सर निपटारा चीन के कानूनी ढांचे के भीतर किया जाता है इसलिए सामूहिक कार्यवाहियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। बाद वाली (यानी सामूहिक कार्यवाहियां- सं.) में भी हम यही प्रवृत्ति पाते हैं जिसके लिए सामान्य तौर पर अधिक मात्रा में संगठनात्मक गतिविधियां, एकता और वर्गीय चेतना की या तो आवश्यकता होती है या इससे वे पैदा होती हैं। 1998 में 6,767 सामूहिक कार्यवाहियां (आम तौर पर हड़ताल या काम धीमा करने की वह गतिविधि जिसमें न्यूनतम तीन मजदूर शामिल रहे हों) हुई जिनमें शामिल मजदूरों की संख्या 2,51,268 थी। सामूहिक कार्यवाहियों में 1992 के मुकाबले यह 900 प्रतिशत की वृद्धि थी। सन् 2000 में सामूहिक कार्यवाहियों की संख्या बढ़कर 8,247 हो गयी जिनमें शामिल मजदूरों की संख्या 2,59,445 थी।" (Page 71, A M R, July-Aug 2004 अनुवाद हमारा)*

नब्बे के दशक के मुकाबले हाल के वर्षों में मजदूरों ने और अधिक पैमाने पर संगठित होकर कई महीनों तक चलने वाली सामूहिक कार्यवाहियों को जन्म दिया है। पॉल और बर्केट एक हवाले का जिक्र करते हैं जो इन कार्यवाहियों

के बारे में बताता है कि इन कार्यवाहियों में "मजबूत सदस्यता, एकता, नेतृत्व और बेहतर स्तर का संगठन" रहा है। इन घटनाओं के अलावा दो शहरों डाकिंङ तथा लियोयांङ शहर की घटनाओं का जिक्र पॉल व बर्केट सहित कई लेखकों ने किया है। डाकिंङ शहर में 50,000 तेल मजूदरों ने और लियोयांङ शहर में 20 सरकारी उद्यमों के 30,000 मजदूरों ने अपने बकाये वेतन, पेंशन और मुआवजे के लिए तथा स्थानीय अधिकारियों व संस्थानों के मैनेजरों के भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ महीनों तक प्रदर्शन किये। दोनों ही घटनाओं में सरकार ने पुलिस और सेना की मदद से मजदूरों के प्रदर्शनों को रोका तथा बुरी तरह से दमन किया। मजदूरों की सभाओं और जुलूसों में सेना के टैंक दौड़ाये गये।

1999 में सरकार ने मजदूरों, किसानों, के बढ़ते प्रदर्शनों के मद्देनजर नये कानून बनाये। इन नये कानूनों के तहत 200 से अधिक लोगों की सभा के लिए स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से तथा 3,000 से अधिक लोगों की सभा के लिए उससे उच्च अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है। इसके साथ ही चीनी सरकार द्वारा देश भर के प्रत्येक शहर में दंगा विरोधी पुलिस में संख्या वृद्धि करने के लिए कहा गया है। जाहिर सी बात है इस दंगा विरोधी पुलिस का इस्तेमाल मजदूरों और किसानों के संघर्षों को कुचलने के अलावा अन्य किसी चीज के लिए नहीं होना है।

शोषक वर्ग के सभी शासकों की तरह चीनी शासक वर्ग 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अपना रहे हैं। शहरों में वे स्थायी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह किसानों को मजदूरों के खिलाफ खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। राबर्ट बाइल ने अपने लेख में निजीकरण के खिलाफ चले संघर्ष तथा मजदूरों के खिलाफ किसानों के इस्तेमाल तथा पुलिसिया दमन की चर्चा की है,

> *" जेंङ-जाऊ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्युपमेंट फैक्टरी के मजदूरों ने अपने अनुभवों में इन विभाजनों की तीक्ष्णता को महसूस किया है। वहां संस्थान को बेच दिया गया और उसकी इमारत को तोड़ दिया गया, इसे अंजाम देने के लिए पुलिस ने इसका विरोध करने वालों को रात में गिरफ्तार कर लिया तथा 'डकैतों से भी बुरे ढंग से मशीनें उठा ले गये। उपकरणों को निकालने के लिए वे 50 युआन प्रतिदिन के हिसाब से किसानों को भी लेकर आये। नतीजतन लम्बा संघर्ष चला। पुलिस ने अपने 'घृणित कार्य' पर जन प्रतिक्रिया से बचने के लिए किसानों को लुटेरों के बतौर खरीदा, उन्हें पहनने के लिए हेलमेट तथा मजदूरों को पीटने के लिए हथियार दिये गये। इन्हें लगभग 30 ट्रकों तथा 500 घोड़ागाड़ियों में लाया गया। यह घटना यह दिखलाती है कि पूरे जेंग-जाऊ में क्या हो रहा है। 24 जुलाई 2001 को मजदूरों द्वारा जो फैक्टरी में काम कर रहे थे उन्हें खतरे की घंटी बजाकर "हर किसी" को बाहर बुला लिया गया। किसानों और मजदूरों के बीच चार घण्टे तक युद्ध चला। उस दिन मजदूर जीत गये। अन्य फैक्टरियों के मजदूर भी सहायता के लिए आ गये और कुल मिलाकर मजदूरों की संख्या 40,000 पहुंच गयी थी। 'सम्पत्ति का नुकसान' पहुंचाने के आरोप में आठ मजदूर गिरफ्तार कर लिये गये। उसी दिन उनके साथ वकील भी थे, पूंजीपति पुनः हार गये। 'हमारे नियम, माओ के नियम हैं' का नारा गूंजा। उस दिन इतने लोग थे कि सरकार डर गयी। पूंजीपतियों ने पुनः दबाव बनाया, दुबारा से मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस ने कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। दस दिन तक किसानों से संघर्ष चलता रहा। इस तरह उन्होंने किसानों को लठैतों की तरह इस्तेमाल कर मजदूरों को फैक्टरी से बाहर निकाल दिया और उसकी हर चीज बेच डाली। 5,600 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मजदूरों के घर सहित फैक्टरी ध्वस्त कर दी और जमीन एक प्राइवेट डेवलपर को दे दी जिसने वहां पर एक स्टोर और बहुंमजिला मकान बना डाला।" (Robort Weil, Conditions of the working classes in China, 2005, www.monthlyreview.org)*

राबर्ट वाइल ने चीन में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें ऐसे मजदूर जिन्होंने सांस्कृतिक क्रांति में हिस्सा लिया था, नये मजदूरों और युवाओं को माओकालीन युग की घटनायें सुना कर और क्रांतिकारी गीत गाकर प्रेरित करते हैं और इस बहस को चीनी शासकों के प्रतिबंध के बावजूद जारी रखे हुए हैं कि चीन का रास्ता पूंजीवाद नहीं समाजवाद ही हो सकता है। उनका कहना यह भी है कि मजदूरों के हिस्सों के बीच सांस्कृतिक क्रांति के तौर-तरीके प्रचलित हैं और वे अपने संघर्षों के दौरान उनका प्रयोग करते हैं। ऐसी ही एक घटना में जेंङजाऊ शहर में संघर्ष के दौरान मजदूरों ने एक पेपर मिल पर कब्जा कर लिया। और इसी शहर में माओ की जयन्ती को मनाने के कार्यक्रम हर वर्ष की तरह शुरू हुए। 2001 में हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने हड़ताल आयोजित की। 10 हजार से अधिक पुलिस वाले मजदूरों को घेरे रहे और उनके साथ मजदूरों की झड़पें हुई। उसके बाद से शहर में माओ की आखिरी बची मूर्ति के इर्द-गिर्द मजदूरों को माओ के जन्म अथवा मृत्यु दिवस के दिन पुलिस इकट्ठा नहीं होने देती है और मजदूर इस सब के बावजूद इकट्ठे होते है और इसको लेकर पुलिस से उनकी झड़पें होती हैं। एक अन्य घटना में 9 सितम्बर 2004 को एक मजदूर कार्यकर्ता ज्यांङ जेनग्याओ (Zhang Zhengyao) ने एक पर्चा बांटा जिसमें माओ के समाजवादी रास्ते की बात की गयी थी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की गयी थी। ज्यांग के समर्थन में कई लोग पूरे चीन से

आये। ज्यांग और उनके अन्य तीन साथियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। ज्यांग और उनके एक साथी को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी। इस घटना ने दुनिया भर में इण्टरनेट के जरिये चर्चा पायी तथा इससे अंदाज लगा कि चीन में माओ समर्थक जहां-तहां मौजूद हैं। जेंगजाऊ शहर के एक मजदूर के इस कथन कि 'चीन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह नहीं है कि जहां पर कभी भी समाजवाद नहीं रहा, का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में चीनी समाज में समाजवाद, सांस्कृतिक क्रांति और माओ की जीवंत स्मृतियां मौजूद हैं। एक बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर व किसान मौजूद हैं जिन्होंने सांस्कृतिक क्रांति में भाग लिया था और वे माओ की चेतावनी कि चीन में 'कभी भी पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो सकती है', से वाकिफ हैं। सुधारों के पहले चरण के काल में भले ही संघर्षों और संघर्षों में शामिल मजदूरों की संख्या कम रही हो परन्तु उसमें लगातार वृद्धि भविष्य की ओर संकेत कर रही है। आज, चीन में कई ऐसे छात्रों के ग्रुप छोटे ही पैमाने पर सही, पैदा हो रहे हैं जो कि मजदूरों से सम्पर्क कायम कर रहे हैं। एक विश्लेषक ने इसकी तुलना 1890 के दशक के रूस के उस काल से की है जब बोल्शेविक पार्टी की स्थापना के पूर्व छोटे-छोटे मार्क्सवादी ग्रुप पैदा हो रहे थे।

कुल मिलाकर, पूंजीवादी पुनर्स्थापना के बाद के काल और विशेषकर पिछले एक दशक की बात की जाय तो मजदूर वर्ग की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को चिन्हित करने पर वे इस प्रकार बनेंगी।

सरकारी ट्रेड यूनियन के दायरे से बाहर आकर मजदूरों द्वारा संगठनबद्ध होने के प्रयास करना। स्वंतत्र ट्रेड यूनियनें स्थापित करना तथा बड़े पैमाने पर कार्यवाही करना। परन्तु अपने शुरूआती प्रयासों में असफल होना।

बिखरे हुए, स्वतः स्फूर्त संघर्षों की प्रधानता। अधिकांश संघर्षों व मजदूरों में आपसी तालमेल का अभाव।

मजदूरों के संघर्षों का चीन के पूर्वी तट में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र में केन्द्रित होना। चीन के अन्य औद्योगिक इलाकों में अपेक्षाकृत संघर्षों का अभाव।

सरकारी उपक्रम के मजदूरों का निजीकरण के खिलाफ जुझारू संघर्ष करना जिसमें डाकिंङ व तायोयांङ की घटना प्रमुख है। इन संघर्षों में मजदूरों की अपनी पूर्व स्थिति को बचाने का प्रयास करना।

सरकारी दमन का तीव्र होना। यूनियन बनाने का प्रयास करने वाले नेताओं की गिरफ्तारी करना तथा स्थानीय अधिकारियों से लेकर प्रांतीय सरकारों द्वारा पुलिस, सेना व स्थानीय गुण्डों का इस्तेमाल मजदूरों के आंदोलन को कुचलने के लिए किया जाना और मजदूरों का दमन के खिलाफ प्रतिरोध करना।

बड़े और विशाल सरकारी उपक्रमों में आज भी ऐसे मजदूर हैं जिनकी स्थिति देश की विशाल सर्वहारा आबादी से एकदम अलग है। ये मजदूर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबन्धित यूनियन ACFTU के सदस्य हैं। ACFTU में भारी संख्या में ऐसे मजदूर हैं जिन्हें 'भात के लोहे के डोंगे' की कई सुविधायें और अधिकार हासिल हैं जो आर्थिक सुधारों के समर्थक हैं। ये चीन के अभिजात मजदूर हैं। अभिजात मजदूरों की एक संख्या देशी-विदेशी उपक्रमों में भी है। इन अभिजात मजदूरों के हित चीन की अधिकार विहीन मजदूर आबादी जिसमें करोड़ों प्रवासी मजदूर शामिल हैं के एकदम खिलाफ खड़े हैं। कई मजदूर नेताओं ने निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान खुद भी फैक्टरियां खरीदी हैं और ठेके प्राप्त किये हैं।

चीनी समाज उस दहलीज पर खड़ा है जहां पर उसे मजदूर वर्ग की एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए। इसके उदय होने पर ही चीन का मजदूर वर्ग वास्तविक राजनीतिक पहलकदमी कर सकेगा।

चीनी समाज के दूसरे बुनियादी वर्ग किसानों के बीच भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। असंतोष के कारणों में; कृषि उत्पादन की लागत का अनाज की तुलना में तेज गति से महंगा होना, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों से अवैध शुल्क सहित करों की निर्ममता पूर्वक उगाही तथा पार्टी पदाधिकारियों द्वारा 'योगदान' की बढ़ती मांग, कृषि सब्सिडी को कम करना तथा कुछ उत्पादों पर सब्सिडी खत्म करने से खाद्य पदार्थों का बहुत मंहगा हो जाना, उद्योगों के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण के बाद किसानों को उचित मुआवजा न देना, प्रमुख हैं।

हाल के वर्षों में मजदूरों की तरह किसानों की ओर से भी संघर्ष करने की कई घटनाएं दर्ज की गयी हैं। अगस्त 2000 में जियांङसी प्रान्त के युआनडू में घटी एक घटना की चर्चा मार्टिन व पॉल ने इस तरह से की है,

> *" अगस्त माह में दस हजार से अधिक गुस्साये किसानों ने दो मंजिला सफेद टाइलों वाले टाउन हॉल की इमारत को घेर लिया। किसान ऊंचे करों तथा प्रशासनिक शुल्कों में कमी की मांग कर रहे थे जो कि खेती के लाभों को चट कर जा रहे हैं ... स्थानीय नागरिकों के अनुसार भयग्रस्त अफसरों ने अपने को इमारत के भीतर बन्द कर लिया। 17 अगस्त को 30 ट्रकों में लदी सशस्त्र पुलिस भीड़ को हटाने के लिए पहुंच गयी। एक किसान को बुरी तरह पीटा गया और एक दर्जन से अधिक को वहां से पकड़ कर ले गये। जैसे ही युआनडू की खबर फैली वैसे ही हजारों गुस्साये किसान निकटवर्ती कस्बों से पहुंच गये ... कई अधिकारियों के घरों पर हमले किये गये। और शीशे तोड़े गये ..."। (पेज - 72,AMR, July-Aug -2004)*

इसी तरह की घटनाओं की चर्चा राबर्ट वाइल ने भी की है। एक प्रमुख घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है :

" ... दूसरी तरफ कागजों में जबकि ग्रामीण स्थितियों में लगातार सुधार हो रहा है, सरकार की औपचारिक नीति किसानों के प्रदर्शनों को जब भी हों, कुचलने की है जो कि बहुत क्रूरतापूर्वक इसलिए भी दबाये जा सकते हैं क्योंकि वे "अदृश्य" होते हैं और बड़े पैमाने पर जनता की निगाह में नहीं आते हैं। ऐसी ही घटना में दिसम्बर 2005 में ग्वाङडोंङ प्रान्त में डोंङजाऊ नामक स्थान में 20 ग्रामीण मारे गये। ये किसान उचित मुआवजा दिये बगैर जमीन को एक पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित करने का विरोध कर रहे थे। ..."

मजदूरों की तरह किसानों के संघर्षों की प्रवृत्ति भी मूलतः स्वतःस्फूर्त है। बिखराव, संगठन, तैयारी व योजना के अभाव के चलते इन संघर्षों को कुचलने में प्रशासन आसानी से कामयाब हो जाता है। 'जहां दमन है, वहां प्रतिरोध है' की तर्ज पर ये संघर्ष पुनः उठ खड़े होते हैं और पहले से बड़े पैमाने पर इनमें जन भागीदारी बढ़ जाती है।

□□□